RNI N.- BIHBIL/2022/88070
राष्ट्रीय द्विभाषिक सामाचार पत्र
www.bordernewsmirror.com

बॉर्डर न्यूज मिरर

"खबरों से समझौता नहीं"

पटना, वर्षः 7 , अंकः 99 , शनिवार, 23 मई 2026 मूल्यः 5:00, पृष्ठः8 9471060219, 9470050309 www.bordernewsmirror@gmail.com

चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मोतिहारी में दो विशेष लोक अदालतें आयोजित... 03

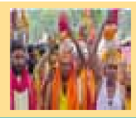

थरबिटिया में सात दिवसीय श्रीराम महायज्ञ का शुभारंभ, 2051 कन्याओं ने निकाली भव्य... 04

मौनी रॉय ने बैकलेस आउटफिट में लूटी महफिल 300 घंटे में तैयार... 07

संक्षिप्त समाचार

भारत-साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता

- पीएम मोदी बोले- समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारत और साइप्रस के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम

मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती न केवल मजबूत है, बल्कि भविष्य की जरूरतों और संभावनाओं के अनुरूप भी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं और अब इन्हें नई दिशा देने के लिए रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।

राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव

- खड़गे-दिग्विजय समेत 24 सांसदों का जून-जुलाई में रिटायरमेंट, 2 सीटों पर उपचुनाव भी

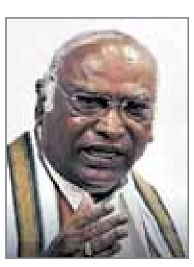

नई दिल्ली। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग (ईडी) ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। रिटायर हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। इन सभी सीटों से मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। इनके अलावा, दो रिक्त सीट पर भी उपचुनाव होगा।

पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा सिस्टम लागू होगा,ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगेंगे

- अमित शाह बोले- हर अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल के भीतर

पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी, ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। दिल्ली में बीएसएफ के रुसतमजी मेमोरियल लेक्चर और बीएसएफ इन्वेस्टिचर सेरेमनी को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है।

रेकॉर्ड स्तर पर बढ़ सकता है दुनिया में तापमान

प्रशांत महासागर में बनने लगा सुपर अल नीनो

वॉशिंगटन (एजेंसी)। वैज्ञानिकों ने मौसम में बड़े बदलाव को लेकर दुनिया को चेताया है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रशांत महासागर में एक संभावित सुपर अल नीनो तेजी से बन रहा है। अल नीनो किस तरह से और कितना दुनिया पर असर डालेगा, यह अस्थिर हवाओं और वायुमंडल में होने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा। तेजी से गर्म हो रहा उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। हवाओं (ट्रेड विंड) में कमजोरी इसे धीमा या तेज फिर कर सकती हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आपसी क्रियाएं बहुत जटिल होती हैं और इनका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए अभी यह पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी कि यह अल नीनो कितना शक्तिशाली हो सकता है।

दुनिया में मच सकती है उथल-पुथल

एनओएए ने अनुमान लगाया है कि इस घटना के 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तक पहुंचने की एक-तिहाई संभावना है। यह सुपर अल नीनो क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा होगा। वहीं एनओएए की अल नीनो-दक्षिणी दोलन की प्रमुख मिशेल एल ह्यूरेक्स ने कहा कि इस पहेली के मुख्य हिस्से अभी तक अपनी जगह पर नहीं आए हैं। अल नीनो की ताकत तब बढ़ती है, जब समुद्र और वायुमंडल गर्मियों के महीनों में एक-दूसरे से ज्यादा जुड़ते हैं। इससे हवा का दबाव, बादलों के पैटर्न और हवाएं बदल जाती हैं। यह प्रतिक्रिया चक्र एक सामान्य अल नीनो को एक बहुत बड़ी घटना में बदल सकता है।

तेजी से बढ़ सकता है तापमान

भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मुख्य अल नीनो क्षेत्रों में समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे सतह के नीचे असामान्य रूप से गर्म पानी का एक बहुत बड़ा भंडार जमा हो रहा है। कई प्रमुख मौसम एजेंसी अनुमान लगा रही हैं कि इस साल के आखिर में प्रशांत महासागर का तापमान औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। साल 1877/78 में दर्ज किए गए पहले बड़े अल नीनो के बाद से केवल तीन घटनाओं- 1982/83, 1997/98 और 2015/16 में तापमान ने 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार की है। यूके मेट ऑफिस में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के प्रमुख एडम स्केफ ने कहा कि यह अल नीनो सबसे शक्तिशाली और रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो सकता है।

पूरी दुनिया में बढ़ेगा तापमान!

अल नीनो आमतौर पर दिसंबर के आस-पास अपने चरम पर होता है लेकिन समुद्र की गर्मी धीरे-धीरे निकलती है। ऐसे में यह अगले सालों में वैश्विक तापमान को बढ़ा सकती है। साल 1998, 2010, 2016, 2023 और 2024 को तेज गर्मी वाले वर्ष गिना जाता है। ये सभी साल अल नीनो की घटनाओं के बाद आए या उनके साथ-साथ विकसित हुए।

एएफपी से इंटरव्यू में जलवायु वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2026 में वैश्विक गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं लेकिन 2027 वह साल है, जिस पर हमें खासतौर से नजर रखनी होगी। इस साल कोई बहुत तेज अल नीनो बनता है तो 2027 में वैश्विक गर्मी का एक नया रिकॉर्ड स्तर आसानी से बन सकता है। यह साफ नहीं है कि पृथ्वी का गर्म होना अल नीनो की तीव्रता पर असर डाल रहा है या नहीं। जलवायु परिवर्तन ने आधार रेखा को इतना बदल दिया है कि मौसमी भविष्यवाणियों के लिए इतिहास अब उतना अच्छा मार्गदर्शक नहीं रहा है।

एनसीईआरटी किताब विवाद पर

सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पुराना आदेश बदला

नईदिल्ली (एजेंसी)। एनसीईआरटी बुक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर पर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले दिया फैसला बदल दिया है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन तीन शिक्षाविदों ने विवादित हिस्सा लिखा। उन्हें हटा दिया जाए और दोबारा काम न दिया जाए।

अब शुक्रवार को तीनों शिक्षाविदों की याचिका पर कोर्ट ने आदेश बदलते हुए कहा कि केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी और सरकारी फंड पाने वाले संस्थान इस मामले में खुद फैसला लें।

मामले में जिन 3 शिक्षाविदों का नाम आया था। उनमें प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार शामिल हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और छात्रों के सामने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि दिखाई।

- **सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पेरेंट्स,जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच करेगी सुनवाई-** शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को 19 लोगों के एक ग्रुप ने चुनौती दी। जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स शामिल हैं।ये याचिका क्लास 9वीं में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध दायर की गई। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अलगे हफ्ते सुनवाई करेगा।

पूरा विवाद क्या था

एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्टबुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। किताब का नाम 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2' है। इसमें 'द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन अवर सोसायटी' चैप्टर के अंदर 'करप्शन इन द ज्यूडिशियरी' का टॉपिक जोड़ा गया है।

'दारुल उलूम देवबंद के 14 फीट नीचे शिव मंदिर'

- सहारनपुर डीएम से खुदाई की मांग! हिन्दू रक्षा दल का दावा

सहारनपुर (एजेंसी)। दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया है कि दारुल उलूम देवबंद के 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर है। हिंदू रक्षा दल ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि वहां खुदाई की जाए। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि अगर जांच होती है और उनकी बात झूठी निकलती है, तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए।

दारुल उलूम पर दावे से छिड़ी नई बहस

वहीं, ललित शर्मा ने कहा कि सांसद के समर्थन में मौजूद लोग वास्तविक हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दारुल उलूम को लेकर किए गए दावे ने इलाके में नई बहस छेड़ दी है।

पेट्रोल-डीजल पर वेट घटा सकते हैं राज्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) कम करने की अपील कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है।

नमाज नहीं, जुमे पर सिर्फ जय सियाराम की गूंज

- 700 साल बाद भोजशाला में हिंदू कर रहे अखंड पूजा
- मुस्लिम समाज ने बांधी काली पट्टी, बंद रहीं दुकानें

धार (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में करीब 700 साल बाद परिसर में नमाज नहीं, सिर्फ पूजा हुई। भोज उत्सव समिति ने शुक्रवार को वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित कर दर्शन-पूजन कराया। मंदिर में सुबह से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। वाग्देवी मंदिर में कारसेवकों के परिजनों का सम्मान भी किया गया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को मंदिर घोषित किया था। मुस्लिम समाज ने फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। अपनी दुकानें भी बंद रखीं। वहीं सुरक्षा के लिए करीब 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष- इधर, हाईकोर्ट के फैसले से निराश मुस्लिम पक्ष गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आदेश को एकतरफा

बताते हुए काजी मोइनुद्दीन ने गुरुवार रात करीब 8:30 बजे विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।शहर काजी वकार सादिक ने कहा- जब सुप्रीम कोर्ट से राहत और स्टे मिलेगा, तब मुस्लिम समाज सम्मान के साथ पहले की तरह नमाज अदा करेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी समुदाय शांति और सौहार्द्र बनाए रखें। शहर हमारा अपना है, इसलिए अमन और भाईचारे को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

ट्विशा केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एम्स दिल्ली की टीम करेगी दोबारा पोस्टमार्ट्म, समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी वापस

जबलपुर (एजेंसी)। भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कई अहम

घटनाक्रम सामने आए हैं। मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की ओर से उसके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी। जानकारी के अनुसार अब समर्थ सिंह भोपाल कोर्ट में सरेंडर कर सकता है।

सुनवाई के दौरान ट्विशा के मायके पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने मामले की गंभीरता और निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए दोबारा पोस्टमार्ट्म कराने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

दोबारा होगा पोस्टमार्ट्म, कोर्ट को सौंपेंगे सीलबंद रिपोर्ट- मृतका का शव लंबे समय से सुरक्षित रखे जाने के कारण उसकी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार अब दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचकर नए सिरे से पोस्टमार्टम करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ताकि जांच प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता बनी रहे। आरोपी समर्थ के जबलपुर कोर्ट में सिरेंडर करने की खबर थी।

जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर निगम) चुनावों को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा सस्पेंस 22 मई पूरी तरह खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के चुनाव टालने वाले प्रार्थना पत्र पर अपना ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुना दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने भजनलाल सरकार की दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने बीते 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जालोर को पहली बार मिली दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन

रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

जालोर (एजेंसी)। पश्चिमी राजस्थान के रेल यात्रियों और खासकर जालोर जिले के बाशिंदों के लिए 22 मई का दिन बेहद ऐतिहासिक और खुशियों की सौगात लेकर आया है। जालोर वासियों की दशकों पुरानी और सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए पहली सीधी रेल सेवा की शुरुआत कर दी है। माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुज-जालोर-पाली मारवाड़-दिल्ली एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एक ओवरनाइट ट्रेन होगी, जो गुजरात के भुज से रवाना होकर जालोर और पाली मारवाड़ के रास्ते सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी।

- **जालोरवासियों का लंबे समय का इंतजार खत्म-** इस नई रेल सेवा के शुरू होने से न केवल राजस्थान, बल्कि गुजरात और दिल्ली के बीच भी रेल कनेक्टिविटी बेहद मजबूत और सुगम हो जाएगी। अब तक जालोर के लोगों को दिल्ली जाने के लिए बसों का सहारा लेना पड़ता था या फिर अन्य शहरों से ट्रेन बदलनी पड़ती थी। यह नई ट्रेन भीलडी, जालोर, पाली मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन के रास्ते दिल्ली तक का सफर तय करेगी। इस ट्रेन के संचालन से स्थानीय जनता और प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।

सीएम धामी बोले-

देवभूमि में सड़कों पर नमाज की इज़ाजत नहीं, चारधाम यात्रियों को न हो कोई परेशानी

देहरादून (एजेंसी)। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब सीएम धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हमने कहा कि नमाज तय जगह पर ही पढ़ी जानी चाहिए। किसी को भी इस व्यवस्था में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। इसलिए इस समय सड़कों को धार्मिक प्रदर्शनों का जरिया बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

स्कूल में मिड-डे-मिल से बच्चे बीमार, ग्रामीण बोले- खाने में जहरीले कीड़े और छिपकली मिली थी

हाजीपुर। वैशाली में महुआ थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलकंठपुर (अब्दुलपुर) में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। कई बच्चों के बेहोश होने की भी खबर है। उन्हें तत्काल अनुमंडल अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल में बीमार बच्चों के पहुंचने से गहमागहमी का माहौल बन गया। बच्चों को लगातार उपचार के लिए भर्ती किया जा रहा है। बच्चों के बीमार पड़ने के कारणों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। एकता शक्ति फाउंडेशन के प्रभारी ने बच्चों के गर्मी से व्याकुल होने और अंडे व फल को लेकर कुछ अभिभावकों द्वारा राजनीति किए जाने की बात कही है। वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि मध्यान्ह भोजन में विषैले कीड़े थे। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीडीओ से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों के मध्यान्ह भोजन में छिपकली निकली थी। जब एक बच्चे ने यह बात शिक्षक को बताई, तो शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। इसी घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जब भी स्कूल में मध्यान्ह भोजन आता है, तो शिक्षक खुद नहीं खाते और बच्चों को खिलाते हैं। ग्रामीणों ने सभी संबंधित शिक्षकों का वेतन बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शक्ति एकता फाउंडेशन के मेस इंचार्ज शिव शंकर कुमार ने बताया कि खाने में किसी प्रकार के कीड़े नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्चा खाना खाने के बाद छुट्टी लेकर स्कूल से अपने घर चला गया था। उसके परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने पेट दर्द होने का हवाला दिया। इसके बाद परिजन तुरंत बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों ने बताया कि बच्चा छुट्टी लेकर घर गया था। इसके बाद शिक्षक और बच्चों के परिजनों में बहस छिड़ गई और आसपास के दर्जनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच गए।

आइसक्रीम फैक्ट्री चोरी मामले में 3 आरोपी अरेस्ट, हाजीपुर पुलिस ने 29,400 रुपये बरामद किए

हाजीपुर। हाजीपुर गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने मगुराही रोड हिलालपुर स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री से चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के 29,400 रुपये भी बरामद किए हैं। यह चोरी बीते मंगलवार की रात हुई थी, जिसमें कुल 3,97,150 रुपये की चोरी हुई थी। सदर 1 एसडीपीओ सुबोध कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के मगुराही रोड हिलालपुर चौक स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले चार लोगों ने कैश रूम का ताला तोड़कर 3,97,150 रुपये चुरा लिए थे। इस संबंध में गंगाब्रिज थाना में कांड संख्या 138/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने मानवीय और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए तीन आरोपियों को चोरी के 29,400 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक, सादुल्लापुर निवासी शत्रुघ्न चौधरी ने अनीश कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चौधरी ने आरोप लगाया कि इन नामजद व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैश रूम का गेट तोड़कर लगभग 30,000 रुपये के सिक्के और 3,67,150 रुपये नकद, कुल 3,97,150 रुपये चुरा लिए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।

पाकिस्तान तस्कर के संपर्क में था मुजफ्फरपुर का नाबालिग

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रतनपुर गांव के रहने वाला नाबालिग (17) का संपर्क पाकिस्तानी तस्कर शहजाद भट्टी से था। बिहार ATS ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है। ATS की टीम नाबालिग से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी नाबालिग का संपर्क पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी से है। उसके नेटवर्क से जुड़कर काम करता था। एजेंसी विदेशी फंडिंग और बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। ATS को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर तकनीकी और डिजिटल सर्विलांस की मदद से जांच की तो मामला सही पाया। इसके बाद ATS की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी नाबालिग के पास से बरामद डिजिटल सबूतों से देश की सुरक्षा व्यस्था को प्रभावित करने की साजिश का खुलासा हुआ है। ATS अधिकारियों के अनुसार, आरोपी नाबालिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। ATS की तकनीकी टीम ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें डिलीट किए गए डेटा, चैट बैकअप और कई डिजिटल फाइलें रिकवर की है। मोबाइल से देश विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राणा हुनैन से लगातार संपर्क में था। ATS की जांच में पता चला है कि आरोपी ने भारत की कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों की फोटो-वीडियो और लोकेशन पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। ATS आरोपी के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, कॉल डिटेल और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और यात्रा इतिहास की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंडिंग भी की जा रही थी। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। बिहार ATS ने आरोपी के खिलाफ जासूसी, देश विरोधी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।

देवर के अफेयर में भाभी की हत्या, पड़ोस की लड़की से लव मैरिज की थी, साला ने घर में घुसकर दागी बुलेट

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गुरुवार देर रात घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी गई। मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी देवर के साला पर है। मृतका की पहचान महेश पासवान की पत्नी मीना देवी(30) के तौर पर हुई है। घटना जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के गौरा वार्ड नंबर-2 की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। प्रेम-प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजन दिनेश पासवान ने बताया मीना के देवर का पड़ोस की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। दोनों ने हाल ही में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। इस रिश्ते का वो विरोध कर रही थी। इसको लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। देर रात लड़की का भाई घर पहुंचा था, जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया और बहस काफी बढ़ गई। इसी दौरान आरोपी ने हथियार निकाल लिया और मीना देवी पर गोली चला दी। गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं, परिजन नीरज पासवान ने बताया कि लड़की पक्ष की ओर से पहले भी धमकी दी गई थी। लड़की के भाई ने पहले ही कहा था कि सबको देख लेंगे। उसी धमकी के बाद रात में घर में घुसकर गोली मार दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। परिजनों के बयान के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार कैंप कर रही है।

80 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार

एजेंसी, पटना

पटना पूर्वी इलाके में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगभग 80 लाख रुपए के प्रतिबंधित इंजेक्शन और कफ सिरप बरामद किए गए हैं। इसके साथ दो सप्लायर भी पकड़े गए हैं। दरअसल, चित्रगुप्त नगर SHO शंकर झा को गुप्त सूचना मिली कि रामकृष्ण नगर इलाके में गोदाम बनाकर नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पूर्वी SP परिचय कुमार के द्वारा गठित पूर्वी इलाके की DIU टीम ने छापेमारी की। एक मकान से भारी मात्रा में लगभग 33500 एम्पुल प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और 3500 से 4000 पीस कफ सिरप बरामद किए हैं। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनकी निशानदेही पर लिंकेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसकी चेन के बारे में बता सकते हैं। हाल के दिनों में पूर्वी इलाके से बड़ी बड़ी खेप बरामद हुई है।

एक सप्लायर सुपौल और दूसरा पटना का रहने वाला: पकड़े गए दोनों सप्लायर की पहचान सुपौल के शेख अब्दुल्ला और राम कृष्ण नगर के रहने वाले ऋषि के तौर पर हुई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में यह इंजेक्शन छुपा कर रखा गया था। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपियों ने पहले बरगलाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तलाशी ली तो सब हैरान हो गए। इस टीम में चित्रगुप्त नगर SHO शंकर झा, बहादुरपुर SHO शुभम झा समेत लगभग दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे।

ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से कर रहे थे सप्लाई, दोनों आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ

पूर्वी SP परिचय कुमार ने बताया कि इसमें रवि और ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर की संलिप्तता सीधे तौर निकलकर आई है। इसमें न्यू श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक गिरीश, रवि (कदमकुआं) की संलिप्तता आई है। पैसे के ट्रांजेक्शन का ट्रेल भी पाया गया है। बल्क में लाकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में स्टोर किया जा रहा था। वहां से एक एक कर के सप्लाई हो रही थी।

'महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त इसी महीने जारी होगी'

एजेंसी, पटना

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार देश का पहला राज्य बना, जहां महिलाओं के लिए इस तरह की रोजगार योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि, महिलाओं को ठगा नहीं गया है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। कई महिलाओं ने इससे रोजगार भी शुरू कर दिया है।

इसी महीने मिलेगी अगली किस्त: मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि, 'महिलाओं को 2 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि देने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने अगली राशि जारी कर दी जाएगी।'

5 किस्तों में मिलेंगे 2.10 लाख रुपए: मंत्री ने योजना की राशि वितरण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि, 'महिलाओं को कुल 2 लाख 10 हजार रुपए पांच किस्तों में दिए जाएंगे। पहले किश्त 10000 का गया दूसरा किस्त 20000 का जाएगा। तीसरा किश्त 40 हजार रुपए का जाएगा। चौथा किसके 60000 का और पांचवा किस्त 80000 हजार रुपए का जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राशि जीविका दीदियों को रोजगार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है।

मंत्री श्रवण कुमार ने किया ऐलान, 5 किस्तों में मिलेंगे 2.10 लाख रुपए

सीएम आवास के पास मिली शराब की खाली 10 बोतलें

एजेंसी, पटना

बिहार में शराबबंदी के बीच मुख्यमंत्री आवास के पास शराब की खाली 10 बोतलें मिली हैं। एक बोतल जमीन पर पड़ी थी। बाकी पेपर में रेप कर के एक कपड़े के थैले में रखी थी। शराब की सभी बोतलें महंगे ब्रांड की हैं। एक बोतल की कीमत का मार्केट प्राइज 4 हजार से 5 हजार के बीच है। शराब की बोतल मिलने की सूचना पर सचिवालय थाना प्रभारी गौतम कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी खाली बोतलों को हटवाया। उन्होंने कहा, मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय में ADG लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को जो जानकारी मिली है, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वहीं रोहिणी आचार्य ने X पर सवाल करते हुए लिखा है, 'कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध शराब के कारोबारियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है।' रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कहा, 'शराबबंदी पर सवाल उठाने से पहले अपने घर का हिसाब तो देख लीजिए।'

सभी महंगे ब्रांड, सचिवालय थाना पुलिस ने हटाया, रोहिणी ने कहा- ये कैसी शराबबंदी है

निशान और किया के शोरूम पर चला बुलडोजर

एजेंसी, पटना

बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग और असुरक्षित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह पटना के कुर्जी मोड़ स्थित निशान और किया के शोरूम पर जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। सुबह के 6 बजे से नगर निगम की टीम द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। Kia शोरूम के जनरल मैनेजर विवेक कुमार ने बताया कि लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिना समय दिये सुबह 6 बजे से 200 फोर्स पहुंची और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज: सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में व्यापक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, एनएचएआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पुलिस मुख्यालय सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि नवंबर 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 34 लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी के अनुपालन में बिहार सरकार ने अब राज्यभर में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथों के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब ट्रक, बस और अन्य भारी वाहन केवल निर्धारित ट्रक ले-बाय और वे-साइड अमेनिटी क्षेत्रों में ही पार्क किए जा सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

हाईवे किनारे अवैध ढाबों-कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, बिहार सरकार ने दिया 20 दिनों का डेडलाइन

20 दिनों के भीतर हटाने होंगे अवैध ढाबे और होटल: बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे क्षेत्र में बने अवैध ढाबों, होटलों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं को 20 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया। यदि तय समयसीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स संयुक्त कार्रवाई करेगी। इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई, पथ निर्माण विभाग और स्थानीय निकाय मिलकर अवैध निर्माण हटाएंगे।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे क्षेत्र में किसी भी नए ढाबा, होटल या व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

बाढ़ में गंगा किनारे अवैध मिट्टी खनन पर छापेमारी

एजेंसी, पटना

पटना के बाढ़ अनुमंडल के ढीबर गांव के समीप गंगा नदी में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। एनटीपीसी थाना क्षेत्र में चल रहे इस अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर एसडीपीओ रामकृष्णा ने देर रात छापेमारी की। हालांकि, कार्रवाई से पहले ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर मिट्टी की कटाई की जा रही थी, वहीं से एनटीपीसी प्लांट को पानी की आपूर्ति होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों से लगातार रातभर गंगा किनारे मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। इस मामले में एनटीपीसी थाना की गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

खेतों में मिले 15 फीट गहरे गड्ढे: छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को किसानों के खेतों में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे मिले। एसडीपीओ ने इसकी सूचना तुरंत खनन विभाग को दी। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि एनटीपीसी डैम के नजदीक इस तरह की खुदाई भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पूर्व में भी बारिश के दौरान ऐसे गहरे गड्ढों में पानी भरने से कई लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि अब किसान रातभर जागकर अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं।

थाना से कुछ सौ मीटर दूर चल रहा था खेल- ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध खनन एनटीपीसी थाने से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाद एसडीपीओ रामकृष्णा ने खुद मोर्चा संभालते हुए देर रात छापेमारी की। एक स्थानीय व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जिस जमीन से मिट्टी काटी जा रही है, उसे एनटीपीसी ने अधिग्रहित कर रखा है। हालांकि, मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान अब भी वहां खेती करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, माफिया एक ट्रिप मिट्टी 800 रुपये में बेचते हैं। इसमें 300 रुपये ट्रैक्टर मालिक को और 500 रुपये माफिया को मिलते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 20 ट्रैक्टर रोजाना चलते हैं और एक ट्रैक्टर लगभग 20 ट्रिप मिट्टी ढोता है। इस हिसाब से प्रतिदिन करीब 400 ट्रिप मिट्टी की बिक्री से लगभग 2 लाख रुपये की कमाई हो रही थी।

15 फीट गहरे गड्ढे मिले, माफिया फरार, थाना से कुछ सौ मीटर दूर चल रहा था खेल

एसडीपीओ रामकृष्णा ने बताया कि, 'सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। मौके पर खनन करते हुए कोई नहीं मिला, लेकिन मिट्टी कटाई के स्पष्ट निशान पाए गए हैं।' उन्होंने कहा कि, 'इस तरह की गतिविधियों से पर्यावरण समेत कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब पुलिस स्वयं इस इलाके की निगरानी करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी कटाई की सूचना तुरंत दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।' एसडीपीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों से हटकर कोई भी अवैध गतिविधि पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटना में छात्रा से बॉयफ्रेंड ने किया रेप, बोली- डराकर संबंध बनाया

एजेंसी, पटना

पटना में SSC की तैयारी कर रही छात्रा पर चाकू से हमला हुआ है। लड़की की उम्र 26 साल है। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर रात को बॉयफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान वो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो प्रेमी ने गर्दन और हाथ पर चाकू से हमला कर दिया। बॉयफ्रेंड ने चाकू की नोंक पर उसके साथ संबंध बनाया। घायल छात्रा बदहवास हालत में इलाज कराने IGIMS पहुंची, जहां से पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मामला शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र की मछली गली इलाके का है।

लड़की ने पुलिस को बताया कि, अक्टूबर 2025 में मेरी पहचान मधेपुरा के रहने वाले मनीष यादव से हुई थी। हम दोनों IGIMS में डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। यहीं काम के दौरान हमारी बातचीत शुरू हुई। इसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए। हम बाहर भी एक-दूसरे से मिलने लगे। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने भी हां कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि हम जल्द शादी कर लेंगे। इस दौरान हम दोनों के बीच कई बार संबंध बने। मैं बिहार SSC की तैयारी करती थी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मैं कदमकुआं इलाके के एक हॉस्टल में रहकर तैयारी करने लगी। इस दौरान भी हमारा मिलना-जुलना जारी रहा। मैं जब भी उससे शादी की बात करती वो गुस्से में आ जाता। हमारा वो दिन खराब हो जाता। मैंने धीरे-धीरे उससे शादी की बात कहना ही छोड़ दिया था। घटना के बाद आरोपी छात्रा पर रातभर रुकने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकलकर हॉस्टल जाने की बात कहती रही।

किशनगंज, अररिया समेत 4 जिलों में झमाझम बारिश

एजेंसी, पटना

बिहार के 14 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों से दोपहर के वक्त घरों में ही रहने की अपील की है। शेखपुरा, सासाराम में तापमान 40°C के पार है। अररिया में मौसम बदला है। 12 बजे बाद मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज यहां बारिश का अलर्ट किया किया था। आकाशीय बिजली से एक शख्स की भी मौत हुई है। किशनगंज में भी बारिश हुई है। सुपौल में भी मौसम बदला और बारिश हुई। इसके अलावा जहानाबाद में भी अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई।

तेज धूप से बिहार के कई शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जमुई के स्कूल में गर्मी से छात्राएं बेहोश हुई हैं। वहीं, गयाजी के टिकारी अनुमंडल क्षेत्र के मखपा गांव स्थित कस्तूरबा विद्यालय में छह छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नालंदा, गयाजी और जहानाबाद में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। जबकि क्लास 6 से आठवीं तक सुबह 10:30 और 11 बजे तक ही पढ़ाई होगी। पटना में भी 26 मई तक क्लास 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

औरंगाबाद में भीषण गर्मी के चलते क्लास 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक सुबह 11.30 तक क्लास का संचालन होगा। जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

मंत्री नंदकिशोर राम बोले-तेजस्वी विद्वान आदमी हैं, कहा- फ्रेम में बने रहने के लिए उनका बोलते रहना जरूरी

एजेंसी, पटना

बिहार सरकार के मंत्री ने तेजस्वी यादव को विद्वान आदमी कहा। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष हैं, विद्वान आदमी हैं, लाजमी है कि बोलते रहना है। आखिर उनके फ्रेम में कैसे लोग आएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उनकी समझ में बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारी समझ में नहीं। वहीं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिए गए टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या कहेंगे यह उनकी अपनी समझ है। विपक्ष द्वारा बिहार सरकार का खजाना खाली होने के बात पर मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, जिन्हें जो समझ है वह बोल रहे हैं।

बिहार में अकादमिक ट्रेडीशन काफी अच्छा है: दरअसल, आज अधिवेशन भवन में बिहार पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी में आज चौथे कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया था। इस दौरान बिहार के राज्यपाल भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने कहा कि बिहार में अकादमिक ट्रेडीशन काफी अच्छा बना हुआ है। मैं जब से राज्यपाल बनकर आया हूं, तब से मैं यह चौथा कॉन्वोकेशन अटेंड कर रहा हूं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। यह एनिमल साइंस का जो डोमेन है वह काफी महत्वपूर्ण है। बिहार अभी भी काफी हद तक रूरल बेस्ड है। इसकी जितनी एनालिसिस और रिसर्च हो, उतनी कम है। किसी भी चीज में आज के समय मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं।

पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में पहुंचे थे

मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार काम करेगी: वहीं, 2 रुपये दूध के दाम बढ़ने पर मंत्री ने पत्रकार से कहा कि यह बात आपके द्वारा मेरे संज्ञान में दी जा रही है। मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार काम करेगी और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मूल्य क्यों बढ़ा है। महंगाई बढ़ने पर उन्होंने कहा कि यह वैश्विक समस्या है दुनिया के सभी देश इससे परेशान है। कुछ परेशानियां अभी रहेगी। कुछ बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। आप सभी को यह बातें बोझ लग रही होगी, लेकिन यह वही बिहार है, जिसे एनडीए गठबंधन को बिखरा हुआ, सिसकता हुआ मिला था। मगर अब बिहार के हालात बदल रहे हैं। अगर कुछ व्यवस्था सुधरती है, तो कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।

संक्षिप्त समाचार

इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रा रिमी की संदिग्ध मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश, एसआईटी गठित

बीएनएम @ मोतिहारी। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा रिमी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले के उद्भेदन और निष्पक्ष जांच के लिए एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। पुलिस के अनुसार छात्रा के मोबाइल फोन से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से छानबीन कर रही है और दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। इस संबंध में एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच आत्महत्या के दृष्टिकोण से करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसी परिस्थिति उत्पन्न की है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।

न्यायालय में बंदियों के उपस्थापन में अनियमितता, 10 पुलिसकर्मी निलंबित

बीएनएम @ मोतिहारी। माननीय न्यायालय मोतिहारी में बंदियों एवं कैदियों के उपस्थापन के दौरान अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और संदिग्ध आचरण के आरोप में पूर्वी चम्पारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायालय में बंदियों के उपस्थापन के दौरान प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मियों पर आरोप था कि वे निजी स्वार्थ एवं प्रलोभन में आकर बंदियों को विशेष व्यक्तियों, जिनमें महिला एवं पुरुष सहित परिजन भी शामिल हैं, से मुलाकात करवा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) द्वारा की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को विभागीय गरिमा के प्रतिकूल तथा पुलिस की छवि धूमिल करने वाला माना गया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कृत्य अनुशासनहीनता, मनमानेपन एवं उदंडता को दर्शाता है। दोषी पाए जाने के बाद जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें हवलदार राम कुमार यादव, मनीभूषण शर्मा, रंजीत कुमार सिंह तथा सिपाही सदानंद कुमार, ललटु कुमार, अदालत कुमार, आदित्य कुमार, संदीप कुमार, रमण कुमार एवं संतोष कुमार आनंद शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा

बीएनएम @ मोतिहारी। मुफ्फसिल (लखौरा) थाना कांड संख्या 430/22 से जुड़े पॉक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो), मोतिहारी ने अभियुक्त भूलन सहनी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। दोषी अभियुक्त भूलन सहनी, पिता स्वर्गीय दसई सहनी, बहुआरी गांव, थाना लखौरा, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी है। मामले में मोतिहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, चार्जशीट तथा विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366(ए) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 376(2) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति कड़ा संदेश माना जा रहा है।

विभिन्न कांडों में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

बीएनएम @ मोतिहारी। "जन विश्वास, संकल्प हमारा" अभियान के तहत पूर्वी चम्पारण पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अलग-अलग मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार कल्याणपुर थाना क्षेत्र में थाना कांड संख्या 46/21 के हत्या मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कांड संख्या 230/26 के उत्पाद अधिनियम मामले में 01 अभियुक्त, थाना कांड संख्या 229/26 के हत्या के प्रयास मामले में 03 महिला अभियुक्त तथा थाना कांड संख्या 231/26 के आर्म्स एक्ट मामले में 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार कल्याणपुर थाना क्षेत्र से कुल 06 अभियुक्त पकड़े गए। इसके अलावा बंजरिया थाना क्षेत्र में थाना कांड संख्या 307/26 के तहत उत्पाद अधिनियम मामले में 02 अभियुक्त तथा थाना कांड संख्या 308/26 में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह बंजरिया थाना क्षेत्र से भी कुल 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि अपराध एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है।

शराब कारोबार के मामले में फरार अभियुक्त गिरफ्तार

बीएनएम @ मोतिहारी। सुगौली थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब कारोबार से जुड़े एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू कुमार उर्फ टेना कुमार के रूप में हुई है, जो सुगौली थाना क्षेत्र के गोडीगावा गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कांड में फरार चल रहा आरोपी इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा उसके विरुद्ध आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। थाना पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ सुगौली थाना में शराब से संबंधित कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कांड संख्या 584/19, 271/25, 51/25, 176/26 एवं 173/26 शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में शराब कारोबार एवं तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहेगी।

नाबालिग दुष्कर्म व अपहरण मामले में अनुसंधान एवं लापरवाही को लेकर दारोगा निलंबित

बीएनएम @ मोतिहारी। नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के बाद अपहरण से जुड़े एक मामले में पूर्वी चम्पारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपरा थाना में पदस्थापित दारोगा रोहित कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान हाल के दिनों में हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर चिंता जताई थी। न्यायालय की टिप्पणी के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई थी। सूत्रों के अनुसार मामले में अनुसंधान एवं कार्रवाई को लेकर लापरवाही के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की। हालांकि विभागीय जांच के बिंदुओं को लेकर विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चीन से निकली लीची को बिहार ने दी विश्व पहचान, मेहसी की सुगंधित शाही लीची बनी स्वाद की महारानी

बूढ़ी गंडक के तट से उठी मिठास की खुशबू, पूर्वी चंपारण में हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था का आधार बनी लीची

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी। यह सर्वविदित है कि "लीची" शब्द मूलतः चीन की देन है। दुनिया के अधिकांश फलों के अलग-अलग देशों में अलग नाम हैं, लेकिन लीची ऐसा फल है जिसका नाम लगभग हर देश में एक जैसा ही प्रचलित है। करीब दो हजार वर्ष पूर्व चीन की धरती पर जन्मी लीची ने वहां से निकलकर जब बिहार की मिट्टी और बूढ़ी गंडक के किनारे का वातावरण पाया, तब उसका स्वाद, रंग, मिठास और सुगंध ऐसी निखरी कि वह पूरे विश्व में पहचान बनाने लगी। आज बिहार की शाही लीची, विशेषकर पूर्वी चंपारण के मेहसी क्षेत्र की लीची, गुणवत्ता और सुगंध के मामले में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीचियों में गिनी जाती है। चीन के गुआंगडोंग और फुजियान प्रांत में सबसे पहले लीची को जंगलों से निकालकर बागवानी के रूप में विकसित किया गया। तांग वंश के सम्राट जुआंग जोंग को लीची अत्यंत प्रिय थी और उनके लिए दक्षिण चीन से घोड़ों पर लादकर लीची राजमहल तक पहुंचाई जाती थी। चीन आज भी प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख मीट्रिक टन लीची का उत्पादन करता है और वहां की वाई ची, हाक यिप तथा नो माई ची जैसी किस्में प्रसिद्ध हैं। लेकिन अब विश्व के लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि बिहार की शाही लीची के स्वाद और सुगंध को चुनौती देना आसान नहीं। भारत में लीची का इतिहास लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। चीन से यह फल अरुणाचल प्रदेश, बंगाल होते हुए बिहार पहुंचा। कहा जाता है कि 1800 ईस्वी के आसपास बिहार में इसकी बागवानी शुरू हुई। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर क्षेत्र में लीची पर व्यापक शोध हुआ और चाइना लीची से विकसित एक नई किस्म "शाही लीची" अस्तित्व में आई। यह बिहार के शाही परिवारों की देन मानी जाती है और आज भी उसी नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में लीची की असली मिठास बूढ़ी गंडक नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से जुड़ी मानी जाती है। पूर्वी चंपारण के सुगौली, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, चकिया, मधुबन और विशेष रूप से मेहसी से गुजरते हुए यह नदी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर तक जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नदी के दोनों ओर लगभग पांच किलोमीटर का क्षेत्र लीची उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। यही कारण है कि मेहसी क्षेत्र की लीची अपनी अलग सुगंध और मिठास के कारण बाजार में विशेष पहचान रखती है। पूर्वी चंपारण में वर्ष 1985 तक गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। लेकिन चकिया, मोतिहारी और सुगौली की चीनी मिलों के बंद होने के बाद किसानों ने लीची की बागवानी को आमदनी का बेहतर साधन बनाया। आज जिले के 18 प्रखंडों में लीची के बाग फैल चुके हैं, जिसमें मेहसी का स्थान प्रथम माना जाता है। अनुमान है कि जिले में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लीची की खेती हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार एक एकड़ में लगभग 200 लीची के पौधे लगाए जाते हैं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पूर्वी चंपारण में लगभग 30 लाख लीची के पौधे हैं। यदि एक पौधे से औसतन 70 किलो उत्पादन माना जाए, तो जिले में

26 मई को होगी स्नातक तृतीय सेमेस्टर की स्थगित परीक्षा

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी। स्नातक सत्र 2024-28 अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर की 18 मई को द्वितीय पाली में होने वाली परीक्षा तकनीकी कारणों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा स्थगित कर दी गई थी। पहले इस परीक्षा की नई तिथि 23 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन डीसीईसीई-2026 प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के कारण परीक्षा तिथि में एक बार फिर बदलाव किया गया है। एलएनडी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मृगेंद्र कुमार के हवाले से मीडिया प्रभारी डॉ. प्रभाकर कुमार ने शुक्रवार को संवाद प्रेषित कर बताया कि तृतीय सेमेस्टर की स्थगित परीक्षा अब 26 मई को द्वितीय पाली में पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

जिले में तेरह कलाकारों को बिहार सरकार द्वारा पेंशन की मिली मंजूरी

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी । कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले में तेरह कलाकारों को पेंशन की मंजूरी दी है। विभाग द्वारा इसकी सूचना जारी कर दी गई है। ज्ञात हो कि गत 28 फरवरी को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के नेतृत्व में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी फहाद सिद्दीकी, चयन समिति के सदस्य वरीय रंगकर्मी डा. राजेश अस्थाना, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के एक एक प्रतिनिधियों द्वारा पेंशन हेतु आए आवेदन पत्रों का 14 पात्र आवेदन का चयन कर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना को भेजा गया था जिसमें 13 कलाकारों अंजनी कुमार, संजय कुमार मिश्र, कल्पना देवी, मंकेश्वर प्रसाद वर्मा उर्फ मुकेश वर्मा, कपिलदेव राम, विनोद कुमार तिवारी, राजेश कुमार वर्मा, प्रेम कुमार वाजपेई, विजय वर्मा उर्फ विजय अमित, राम टहल राम, दिनेश कुमार आज़ाद उर्फ डीके आजाद, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं संजय उपाध्याय को इस महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जानकारी साझा करते हुए चयन समिति के सदस्य डा. राजेश अस्थाना ने बताया कि पहली बार कलाकारों को पेंशन मिलने से जिले के कलाकारों में काफी हर्ष का माहौल है।

चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मोतिहारी में दो विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी

बीएनएम @ मोतिहारी @ अवनीश कुमार सिंह

मोतिहारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोतिहारी द्वारा चेक बाउंस मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए विशेष पहल की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वर्ष 2026 में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु दो विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। पहली विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 तथा दूसरी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। इसी को लेकर सोमवार को एडीआर भवन, मोतिहारी में ऑफिस क्लर्क एवं बेंच क्लर्कों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नितिन त्रिपाठी ने की। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले के विभिन्न न्यायालयों में चेक बाउंस से संबंधित 3000 से अधिक लंबित मामलों की पहचान की जा चुकी है। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों को भौतिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से भी लोगों को जागरूक और सूचित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर कराया जा सके। समीक्षा के दौरान सभी न्यायालयों से लंबित एनआई एक्ट मामलों की अद्यतन सूची प्राप्त करने तथा विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को नोटिस तामिला एवं पक्षकारों से संपर्क प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में कहा गया कि विशेष लोक अदालत चेक बाउंस मामलों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है, जहां बिना लंबी मुकदमेबाजी के आपसी सहमति से विवादों का निपटारा संभव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोतिहारी ने आम नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 18 जुलाई और 21 नवंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामलों का सरल, सस्ता एवं शीघ्र निष्पादन कराएं।

नगर निगम की मासिक बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, लंबित योजनाओं पर जताई नाराजगी

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी। नगर निगम मोतिहारी सभागार में शुक्रवार को महापौर प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में मासिक साधारण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में नरकटिया विधायक विशाल कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान नगर विकास, आधारभूत संरचना, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक सुविधाओं एवं लंबित योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनहित से संबंधित कार्यों में हो रही देरी एवं विभागीय लापरवाही पर सदस्यों ने गंभीर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में पिछले दो वर्षों से लंबित शवदाह गृह निर्माण कार्य का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों ने बताया कि ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार के कारण निर्माण कार्य बाधित है। कई बार सूचना देने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बाजार समिति रोड में सड़क के बीच स्थित विद्युत पोल के कारण सड़क निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस पर नगर आयुक्त आशीष कुमार को ऊर्जा विभाग के सचिव से पत्राचार कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। नगर भवन (टाउन हॉल) के अधूरे निर्माण एवं लंबित निविदा प्रक्रिया पर भी बैठक में चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि योजना चयनित होने के बावजूद निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। टाउन हॉल के अभाव में शहरवासियों को छोटे कार्यक्रमों के लिए महंगे सभागार एवं होटलों पर निर्भर रहना पड़ता है। बैठक में नगर आयुक्त को सभी प्रक्रियाएं पूरी कर जल्द निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया। मुख्य नाला निर्माण योजनाओं में हो रही देरी पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। पूर्व में चयनित योजनाओं पर अब तक कार्य शुरू नहीं होने पर चिंता जताते हुए नगर आयुक्त को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में अधिष्ठापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। महापुरुषों की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठा। कई बैठकों में चर्चा के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई और संबंधित लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण योजनाओं में लंबित कार्यादेश का मामला भी बैठक में उठा। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि सभी संवेदकों को अविलंब कार्यादेश जारी किया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। लगभग छह माह पूर्व 18 उत्क्रमित वार्डों में प्रति वार्ड 200 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा होने के बावजूद कई क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच सकी है। इस पर सभी 46 वार्डों में सर्वे कराकर शेष बचे विद्युत पोलों पर नई स्ट्रीट लाइट योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी वार्डों में नई योजनाओं के चयन को लेकर निर्णय लिया गया कि वार्ड पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में जलजमाव वाली गलियों, मुख्य सड़क एवं नाला तथा अधिक आवागमन वाले मार्गों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का चयन कराएंगे। नगर आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त आशीष कुमार, वार्ड पार्षदगण, निगम के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों ने नगर विकास कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वय को आवश्यक बताते हुए शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।

जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 72 आवेदनों पर हुई सुनवाई

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित "जनता के दरबार में जिला प्रशासन" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शहर के समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन सभागार में कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न अंचलों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) शैलेन्द्र कुमार भारती एवं वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार ने प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। एडीएम पीजीआरओ ने कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का विधिसम्मत समाधान कराया जाएगा। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण वाद एवं राजस्व विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इन मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ आवेदन अग्रसारित करने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग को दिया गया।

मानव दिवस सृजन में फिसड्डी पूर्वी चंपारण, 187 पंचायत रोजगार सेवकों का मानदेय स्थगित

बीएनएम @ मोतिहारी

मोतिहारी। उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में शहर के समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र भवन सभागार में मनरेगा एवं जल संसाधन विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि मानव दिवस सृजन के मामले में पूर्वी चंपारण जिला राज्य में सबसे निचले पायदान पर है। इस पर डीडीसी ने गहरी नाराजगी जताते हुए प्रखंड एवं पंचायतवार प्रगति की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि जिले की 187 पंचायतों में मानव दिवस सृजन 50 से कम, 116 पंचायतों में 50 से 100 तथा केवल 81 पंचायतों में 100 से अधिक रहा। खराब प्रदर्शन करने वाले 187 पंचायत रोजगार सेवकों से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगले आदेश तक उनका मानदेय स्थगित कर दिया गया। वहीं सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी मानदेय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति आने तक रोक दिया गया। बैठक में मेहसी के कनीय अभियंता किशुन दास एवं पहाड़पुर के पंचायत तकनीकी सहायक शमशेर आलम से योजना प्राक्कलन तैयार करने में लापरवाही को लेकर जवाब-तलब किया गया। साथ ही सभी पंचायत तकनीकी सहायकों एवं कनीय अभियंताओं का मानदेय भी पर्याप्त प्राक्कलन नहीं बनाने और कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में स्थगित किया गया। डीडीसी ने कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पंचायत रोजगार सेवकों के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। चकिया, ढाका और कोटवा के कार्यक्रम पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर निष्क्रिय पीआरएस की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। बैठक में कई पंचायत रोजगार सेवकों ने शिकायत की कि कुछ मुखिया योजना क्रियान्वयन एवं अभिलेख खोलने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को ऐसे मुखियाओं को चिन्हित कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया, ताकि मनरेगा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। डीडीसी ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को मनरेगा से 90 दिनों की मजदूरी उपलब्ध कराने, मजदूरों का ई-केवाईसी कराने तथा लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा में औसत से कम मानव दिवस सृजन वाले प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को 25 मई तक कम-से-कम 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया। जल संसाधन एवं मनरेगा अभिसरण योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 614 योजनाओं में से अब तक 294 योजनाओं की इंट्री एवं जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को तत्काल एमआर निर्गत करने तथा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को शेष योजनाओं की इंट्री, जियो टैगिंग एवं कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस अधीक्षक ने किया वाहनों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीएनएम @ बेतिया। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी चंपारण द्वारा शुक्रवार को पुलिस केंद्र बेतिया में थाना, पुलिस अंचल कार्यालय एवं पुलिस केंद्र के वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाहनों की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों एवं रखरखाव की गहन जांच की गई। वाहन परेड के दौरान चालकों द्वारा सायरन लाइट, हूटर, लाठी, बॉडी प्रोटेक्टर, प्राथमिक उपचार किट सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जांच कराई गई। इसके अलावा वाहनों के रखरखाव एवं परिचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान चालक एवं परिवहन शाखा के कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए वाहनों को हमेशा बेहतर स्थिति में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में तत्परता बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, परिवहन शाखा के परिचारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर हथियार लहराना युवक को पड़ा महंगा, गिरफ्तार

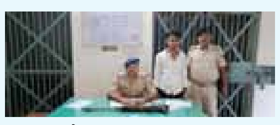

बीएनएम @ तुरकौलिया। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से एक टॉयगन भी जब्त किया गया है। अपर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक युवक हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान चौकीदारों के माध्यम से कराई गई। इस दौरान उसकी पहचान जयसिंहपुर करमवा निवासी हरदेव यादव के पुत्र चुनचुन कुमार उर्फ बली कुमार के रूप में हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियार लहराना तथा वीडियो वायरल कर आम लोगों में भय और दहशत फैलाना कानूनन अपराध है। कार्रवाई के दौरान युवक के पास से टॉयगन बरामद किया गया। अपर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक को धारा 41 के तहत लाभ देते हुए बांड भरवाकर घर भेज दिया गया है।

पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप, जांच में प्राक्कलन उल्लंघन के संकेत

बीएनएम @ तुरकौलिया। प्रखंड की तुरकौलिया मध्य पंचायत स्थित एबी हॉस्पिटल बोरिंग चौक के पास बनी पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर सरकारी धन के दुरुपयोग और अनियमितता के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई प्रारंभिक जांच में प्राक्कलन के उल्लंघन के संकेत मिलने के बाद मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पंचायत समिति सदस्य की शिकायत पर शुक्रवार को प्रखंड तकनीकी सहायक (जेई) दिग्विजय कुमार एवं निकिता कुमारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारियों ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर बीडीओ संतोष राज को सौंप दी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य निजी जमीन पर कराया गया तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच के दौरान कई तकनीकी और प्रक्रियागत कमियां सामने आईं। बताया गया कि जेई की अनुपस्थिति में ही सड़क की ढलाई करा दी गई थी। साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित अभिकर्ता का स्पष्ट पता नहीं चल सका और योजना का शिलापट्ट भी स्थल पर नहीं लगाया गया था। तकनीकी जांच में यह भी सामने आया कि पीसीसी ढलाई के नीचे मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। आरोप है कि सड़क के नीचे केवल ईंट के टुकड़े और प्लास्टिक बिछाकर बिना वाइब्रेटर मशीन के ढलाई कर दी गई, जो प्राक्कलन और गुणवत्ता मानकों के विपरीत है। मामले को लेकर सेनवरिया निवासी लालाबाबू शर्मा ने पूर्व में जिलाधिकारी, डीडीसी, डीपीआरओ और बीडीओ को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की थी। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई। बीडीओ संतोष राज ने बताया कि उन्हें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने की संभावना है।

बाइक व 30 लीटर देसी शराब जब्त, तस्कर फरार

बीएनएम @ तुरकौलिया। पुलिस ने थाना क्षेत्र के बहुरूपिया मसान माई स्थान के समीप छापेमारी कर एक बाइक तथा 30 लीटर देशी चुलाई शराब जब्त की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी की पहचान बहुरूपिया गांव निवासी उपेंद्र राम के रूप में की है। इस संबंध में एसआई मंजय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उपेंद्र राम बाइक से शराब लाकर मसान माई स्थान स्थित पानी टंकी के समीप चोरी-छिपे बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सीडी डीलक्स बाइक की डिक्की से 2 लीटर, प्लास्टिक के थैले से 3 लीटर तथा झाड़ी में छिपाकर रखी गई 25 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष संपत कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर बाइक समेत कुल 30 लीटर देशी शराब जब्त कर ली गई है। फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

नोट डबलिंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बीएनएम @ सुगौली। सुगौली थाना पुलिस ने नोट डबलिंग की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में सुगौली थाना कांड संख्या 279/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उपेन्द्र सहनी के रूप में हुई है। वह केसरिया थाना क्षेत्र के चांद परसा गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को नोट डबलिंग का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध दिघवारा थाना कांड संख्या 321/25 में धोखाधड़ी एवं छिनतई का मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तथा आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है।

निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सासाराम में रिश्वत लेते दो मामलों में तीन गिरफ्तार

बीएनएम @ पटना/सासाराम @ राकेश कुमार

पटना/सासाराम। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतास जिले में एक ही दिन दो अलग-अलग मामलों में तीन लोगों को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाई गुरुवार को सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। इस सफलता पर महानिदेशक ने निगरानी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पहले मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 061/26 के तहत आकाश कुमार रौनियार एवं उनके निजी घरेलू सहायक सोनू कुमार को 3 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों को सासाराम के बेदा मोरसराय स्थित निजी आवास से पकड़ा गया। निगरानी ब्यूरो के अनुसार परिवादी राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक दाखिल-खारिज मामले में 50 हजार रुपये तथा एक विशेष दाखिल-खारिज वाद में 8 लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। सत्यापन में प्रथम किस्त के रूप में 3 लाख रुपये मांगने की पुष्टि होने के बाद पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में धावादल गठित कर कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई में निगरानी थाना कांड संख्या 060/26 के तहत सतीश कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी को सदर अस्पताल सासाराम स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सामने शिव मंदिर के पास सड़क किनारे रंगेहाथ पकड़ा गया। इस मामले में परिवादिनी सुनीता कुमारी ने शिकायत की थी कि उनके स्थानांतरण को रुकवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। सत्यापन के बाद आरोप सही पाए जाने पर पुलिस उपाधीक्षक विकाश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी लोजपा (आर): लोहा पांडेय

बीएनएम @ रामगढ़वा

रामगढ़वा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। यह बातें लोजपा (आर) के प्रदेश महासचिव सह उत्तर प्रदेश के महोबा जिला संगठन प्रभारी पंकज कुमार पांडेय उर्फ लोहा पांडेय ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी हुई है। पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले मैदान में उतरेगी, इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। हालांकि संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में तेजी से चलाया जा रहा है। लोहा पांडेय ने कहा कि सूबे के प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर संगठन को सक्रिय एवं गतिशील बनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक समीक्षा के दौरान लोजपा (आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पक्ष में समाज के हर वर्ग का व्यापक जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यही जनसमर्थन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काफी कारगर साबित होगा।

शस्त्र अनुज्ञप्ति की आड़ में कारतूसों की हेराफेरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

बीएनएम @ मोतिहारी/हरसिद्धि

मोतिहारी/हरसिद्धि। पूर्वी चम्पारण पुलिस ने शस्त्र अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लंघन कर कारतूसों की अवैध खरीद-बिक्री एवं हेराफेरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के औरैया निवासी मो. कलाम, पिता जमशेद मियां के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 21 मई 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि मो. कलाम अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति की आड़ में कारतूसों की खरीद-बिक्री और हेराफेरी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज रवि कुमार के नेतृत्व में बीडीओ गुलशन कुमार एवं हरसिद्धि थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान आरोपी की शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका की जांच की गई, जिसमें वर्ष 2020 से अब तक खरीदे गए कारतूसों और शस्त्र दुकान में जमा कराए गए कारतूसों के रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया। साथ ही कुछ कारतूसों को अवैध रूप से अपने पास रखने की भी पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से 28 जिंदा कारतूस, एक अनुज्ञप्ति पुस्तिका तथा शस्त्र दुकान की प्राप्ति रसीद जब्त की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज रवि कुमार ने बताया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की आड़ में कारतूसों की अवैध हेराफेरी की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई की गई थी। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बरामद कारतूसों एवं दस्तावेजों को विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध हथियार और कारतूस कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के अनुसार आरोपी मो. कलाम का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध तुरकौलिया थाना कांड संख्या 66/22 में हत्या के प्रयास, हरसिद्धि थाना कांड संख्या 37/23 तथा हरसिद्धि थाना कांड संख्या 708/25 में आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में कथित गबन, सीडीपीओ व बीसी पर उठे गंभीर सवाल

बीएनएम @ रामगढ़वा @ अमलेश कुमार

रामगढ़वा। प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत कथित अनियमितताओं और फर्जी लाभुकों के नाम पर करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार योजना के नाम पर फर्जी लाभार्थियों के बीच राशि का अनुचित वितरण किया गया तथा आवेदन प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक के कई कार्य एक ही संचालक के माध्यम से किए गए। मामले के केंद्र में प्रखंड की सीडीपीओ रश्मि कुमारी और बीसी राहुल कुमार का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि लाभार्थियों के आवेदन, सत्यापन और भुगतान संबंधी अधिकांश प्रक्रियाएं बीसी राहुल कुमार के स्तर से संचालित होती थीं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई ऐसे नाम आवेदन पत्रों में दर्ज हैं, जिनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। वहीं आवेदन-पत्रों और भुगतान अभिलेखों में भी कई प्रकार की असंगतियां पाई जा रही हैं। जब सीडीपीओ रश्मि कुमारी से फोन पर योजना में कथित अनियमितताओं तथा पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित महिलाओं की संख्या के संबंध में जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कॉल काट दिया। बाद में दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस व्यवहार को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीसी राहुल कुमार ने मामले में पूछे जाने पर कहा कि लाभार्थियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी और आंकड़ों के लिए सीडीपीओ कार्यालय से संपर्क किया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना के संचालन में उनकी भूमिका काफी सक्रिय रही है, जिससे संदेह और गहरा गया है। इसी मामले में पारदर्शिता की मांग को लेकर एक व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत लाभार्थियों की सूची, भुगतान आदेश तथा बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेजों की मांग की गई थी। आरोप है कि आरटीआई दायर किए जाने के बावजूद अब तक संतोषजनक जवाब अथवा विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं तो संदेह और गहराता जाएगा। हालांकि अब तक प्रखंड सीडीपीओ रश्मि कुमारी और बीसी राहुल कुमार की ओर से कोई लिखित स्पष्टीकरण या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर क्षेत्र में जांच की मांग तेज हो गई है।

रामगढ़वा में खेल का महाकुंभ: डीसीसी क्रिकेट क्लब का भव्य उद्घाटन

बीएनएम @ रामगढ़वा

रामगढ़वा। प्रखंड के डुमरी लक्ष्मीपुर गांव में खेल प्रेमियों के लिए उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, जहां 'डीसीसी क्रिकेट क्लब' का भव्य उद्घाटन युवा समाजसेवी राम विकास उर्फ थारू यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी ने आयोजन को यादगार बना दिया। समारोह के दौरान रामगढ़वा एसआई अजीत सिंह, बिहार टेनिस के वरीय खिलाड़ी मेराज हेलीकॉप्टर, सरफराज बाहुबली, सचिन सिंह, समाजसेवी अरशद अली उर्फ मुन्ना, राजन श्रीवास्तव, बलराम यादव, जिला परिषद पति कमरुद्दीन मंसूरी, मुकेश यादव, सावन यादव, जयकिशोर यादव, संतोष सिंह, बिट्टू सिंह, राशिद कमाल, रंजीत यादव, उमेश यादव, अंकेश यादव और अजीत यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, धैर्य और भाईचारे की भावना विकसित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आयोजन समिति ने बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट को चंपारण के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह है कि मुकाबले दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे, जिससे देर रात तक मैदान में क्रिकेट का रोमांच बना रहेगा। इसके अलावा आयोजकों द्वारा किसी भी टीम से एंट्री फीस नहीं ली जा रही है, जिससे क्षेत्र की अधिक से अधिक टीमें इसमें भाग ले सकें। टूर्नामेंट में चंपारण की कई दिग्गज टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में मुज़फ्फरपुर और नरकटिया की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। प्रतियोगिता को और आकर्षक बनाने के लिए आयोजकों ने विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार स्वरूप नई स्प्लेंडर बाइक, उपविजेता टीम को स्कूटी तथा मैन ऑफ द मैच को फ्रिज देने की घोषणा की है। फिलहाल टूर्नामेंट की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मैदान, पिच और दर्शकों की सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और इस खेल महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है।

थरबिटिया में सात दिवसीय श्रीराम महायज्ञ का शुभारंभ, 2051 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा

बीएनएम @पकड़ीदयाल @ अजीत कुमार सिंह

पकड़ीदयाल। प्रखंड क्षेत्र के थरबिटिया पंचायत स्थित टोला मठ में आयोजित सात दिवसीय श्रीराम महायज्ञ का शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में 2051 कुंवारी कन्याओं ने गाजे-बाजे, भक्ति गीतों और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। विशाल कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर थरबिटिया चौक होते हुए चकनाहा नदी तट तक पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आचार्य घनश्याम शास्त्री, अखिलेश्वर पांडे एवं शुभम पांडे द्वारा विधिवत जलबोझी कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में भाग लिया। यज्ञ समिति के सदस्यों ने बताया कि सात दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन पूजा-अर्चना, प्रवचन, भजन-कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है।

सीमावासियों के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित, 34 लोगों में मोतियाबिंद की पहचान

बीएनएम @ रक्सौल/बीरगंज

रक्सौल/बीरगंज। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. 13 गण हेडक्वार्टर पर्सा के तत्वावधान में "सीमावासियों के साथ सशस्त्र प्रहरी" कार्यक्रम के अंतर्गत पर्सा जिले के सिरसिया क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले विपन्न एवं सीमांतकृत समुदाय को ध्यान में रखकर आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच एवं परामर्श सेवा प्रदान की गई। यह शिविर तिलगंगा आँखा अस्पताल तथा सामुदायिक आँखा केन्द्र के संयुक्त प्राविधिक सहयोग से सम्पन्न हुआ, जबकि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी सिरसिया द्वारा कार्यक्रम का सहजीकरण किया गया। शिविर के दौरान एक दिवसीय मोतियाबिंद शल्यक्रिया जांच एवं पहचान कार्यक्रम भी चलाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. 13 गण हेडक्वार्टर पर्सा के गणपति मोहन बहादुर श्रेष्ठ उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रहरी निरीक्षक समराज खड्का, मेडिकल संयोजक महेश सिंह धामी तथा वरिष्ठ प्रहरी नेत्र राणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में कुल 211 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें 34 लोगों में मोतियाबिंद की समस्या पाई गई। आयोजकों ने बताया कि मोतियाबिंद से पीड़ित सभी मरीजों की निःशुल्क शल्यक्रिया तिलगंगा आँखा अस्पताल में कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य मरीजों को आवश्यकता अनुसार आई ड्रॉप एवं दवाइयां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार के सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आगे भी जारी रखे जाएंगे। स्थानीय लोगों ने भी निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा मिलने पर खुशी जताते हुए इसे ग्रामीण एवं सीमांतकृत समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।

बीरगंज कपड़ा बैंक का मासिक निःशुल्क कपड़ा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

बीएनएम @ रक्सौल/बीरगंज

रक्सौल/बीरगंज। बीरगंज कपड़ा बैंक द्वारा बीरगंज के घण्टाघर परिसर में नियमित मासिक निःशुल्क कपड़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह की तरह इस शुक्रवार को भी आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद, असहाय एवं विपन्न परिवारों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए एवं पुराने मिलाकर लगभग 600 थान कपड़ों का वितरण किया गया। बैंक के कोषाध्यक्ष मनोज मिश्र ने बताया कि बैंक विगत कई वर्षों से समाजसेवा के उद्देश्य से निःशुल्क कपड़ा वितरण का कार्य कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बैंक के कार्यालय बीरगंज–8 से प्रत्येक रविवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा शनिवार को दोपहर 1 बजे तक जरूरतमंदों को निःशुल्क कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष लालबाबू सिंह ने की, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता, प्रकाश उपाध्याय, जसपाल सिंह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा के सभापति बृजकिशोर पटेल, नेपाल बार एसोसिएसन पर्सा के सदस्य आशुतोष तिवारी, बीपीएस +2 कॉलेज के संचालक दीपक पटेल, युवा समाजसेवी हुकुम सिंह राजपुत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी ने कहा कि "जिसके पास अधिक कपड़े हैं, वह दान करे और जो जरूरतमंद हैं, वे निःशुल्क लेकर जाएँ" के मूल मंत्र के साथ बीरगंज कपड़ा बैंक पिछले सात वर्षों से लगातार समाजसेवा कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था केवल कपड़ा वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि आगलागी और बाढ़ जैसी आपदाओं में भी पीड़ित परिवारों तक सहायता पहुंचाती रही है। उन्होंने लोगों से अपनी आय का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करने की अपील की। वहीं दीपक पटेल ने "कोई नंगा ना रहो" अभियान की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया तथा बैंक को स्पीकर और माइक्रोफोन उपलब्ध कराने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष लालबाबू सिंह ने सभी दाताओं, शुभेच्छुओं, संचारकर्मियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

नीतिगत बहसें हाशिये पर चली गई

पहले चुनाव बिल्कुल दोषमुक्त होते थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब उन्हें ऐसे युद्ध की तरह भी नहीं लड़ा जाता था, जिसमें विरोधी को समूल नष्ट कर देने की भावना हो। कभी चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव समझा जाता था। तब चुनाव बिल्कुल दोषमुक्त थे या वे पूरी तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से आयोजित होते थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तब उन्हें ऐसे युद्ध की तरह भी नहीं लड़ा जाता था, जिसमें विरोधी को समूल नष्ट कर देने की भावना हो। अब ऐसा ही नजारा खास कर वैसे राज्य में देखने को मिलता है, जहां कोई गैर-भाजपा दल अब तक मजबूती से खड़ा रहा हो। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव कुछ ऐसे ही माहौल में संपन्न हुआ।

एसआईआर प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में निर्वाचन आयोग की विवादित भूमिका से लेकर अर्धसैनिक बलों द्वारा घेराबंदी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की एकतरफा जैसी दिखने वाली कार्रवाइयों के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। भाजपा नेतृत्व ने अब अपनी पहुंच से बाहर रहे इस किले को जीत लेने की व्यूह-रचना में किसी राजनीतिक मान-मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। ये कहने का अर्थ कतई यह नहीं है कि ममता बनर्जी नैतिक या मर्यादित राजनीति करती हैं। उनकी सियासत में भी बाहुबल और तोड़-जोड़ का उतना ही पुट रहा है। उनकी सफलता में ऐसे रुझानों का योगदान है। बहरहाल, यही ध्यान देने की बात है।

अब चुनावों में ऐसी प्रवृत्तियां ही निर्णायक महत्त्व की हो गई हैं। इसका शिकार विकास और राष्ट्र-निर्माण से संबंधित मुद्दे बने हैं। नीतिगत बहसें हाशिये पर चली गई हैं। जन-कल्याण के नाम पर अधिक से अधिक यही नजर आता है कि तमाम पार्टियां बैंक खातों में नकदी डालने के वादे बढ़-चढ़ कर करती हैं। उन्हें उससे भी ज्यादा भरोसा जाति-धर्म जैसे बांटने वाले मुद्दों पर लोगों को गोलबंद करने की रणनीति पर रहता है। ऐसे संकेत हैं कि इस बार केरल के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे पहचान-गत मुद्दे प्रमुख हो गए। यानी जिस राज्य की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में शिक्षा और स्वास्थ्य, और विकास संबंधी योजनाएं रहती थीं, वहां भी अगड़े- पिछड़े, हिंदू- मुस्लिम- ईसाई जैसी अस्मिताओं पर ध्रुवीकरण के संकेत मिले। ऐसे में उत्सव जैसे माहौल का गायब हो जाना लाजिमी ही है। उलटे अब हर चुनाव एक तरह का जख्म छोड़ कर जाने लगा है!

जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

- चुनौती याचिका 20 मई 2026 को खारिज- संवैधानिक वैधता, सामाजिक न्याय और भारत की नई नीति- व्यवस्था की दिशा क़ा व्यापक समग्र विश्लेषण

भारत की जनगणना 2027 डिजिटल इंडिया और डेटा- आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2026 क़ा यह फैसला केवल एक याचिका खारिज करने तक सीमित नहीं है।बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और डेटा- आधारित शासन प्रणाली के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णय

वैश्विक स्तरपर भारत में वर्षों से चल रही जातिगत जनगणना की बहस को बुधवार 20 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला, जब भारतीय सुप्रीमकोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने केवल एक कानूनीविवाद का अंत नहीं किया,बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि भारत में होने वाली जनगणना 2027 पूरी तरह संवैधानिक,कानूनी और नीतिगत अधिकारों केदायरे में संचालित की जा रही है। बता दें इसके पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल, 2026) को केंद्र को जाति जनगणना रोकने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दियाथा और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए याचिकाकर्ता की कड़ी आलोचना की। पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर तीखी बहस चल रही थी। कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय का आधार बता रहे थे, जबकि विरोधी पक्ष इसे सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला कदम कह रहा था। किंतु सर्वोच्च अदालत के ताजा निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की सामाजिक संरचना, विशेषकर पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति को समझने के लिए डेटा एकत्र करे, ताकि उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत की जनगणना 2027 केवल एक पारंपरिक जनगणना नहीं मानी जा रही,बल्कि इसे डिजिटल इंडिया और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही जनगणना व्यवस्था अब तकनीकी रूप से आधुनिक स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है।

साथियों इस बार की जनगणना दो बड़े चरणों में आयोजित की जा रही है।पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ,जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवासीय गणना की प्रक्रिया अपनाई गई। 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक चले इस चरण में देशभर के घरों,संपत्तियों,भवनों, आवासीय सुविधाओं, जल स्रोतों, बिजली, इंटरनेट, शौचालय, रसोई, वाहन और सामाजिक- आर्थिक आधारभूत संरचनाओं से संबंधित डेटा संकलित किया गया।यह चरण केवल जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देश की जीवन- स्थितियों का व्यापक सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण भी बन गया।जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट आधारित डेटा एंट्री, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों को अब सामाजिक न्याय और संसाधन वितरण के दृष्टिकोण से सटीक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना करना या न करना सरकार का नीतिगत अधिकार है।अदालत ने कहाकि जब तक कोई नीति संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं करती, तब तक न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत की यह टिप्पणी भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी मजबूती देती है, जहां नीति निर्माण कार्यपालिका का क्षेत्र माना जाता है और न्यायपालिका केवल वैधानिकता की समीक्षा करती है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की वास्तविक संख्या कितनी है,ताकिउनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जाति आधारित गणना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है।यदि सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंकड़े जुटाना चाहती है, तो यह उसका वैध प्रशासनिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नीति के संभावित दुरुपयोग की आशंका मात्र से उसे रोका नहीं जा सकता। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यही था कि जातिगत आंकड़ों का राजनीतिक और सामाजिक दुरुपयोग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त सामाजिक डेटा उपलब्ध है, इसलिए अलग से जातिगत गणना की आवश्यकता नहीं है। किंतु अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सरकार को समकालीन और प्रमाणिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराने डेटा के आधार पर प्रभावी नीति निर्माण सटीक रूप से संभव नहीं है। साथियों, यह फैसला सामाजिक न्याय की राजनीति और प्रशासनिक नीति दोनों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक आधार क्या होना चाहिए। अनेक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि बिना अद्यतन जातिगत आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियां अधूरी रहती हैं। स्वतंत्र भारत में 1931 के बाद व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे, जिसके कारण पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार विवाद बना रहा। ऐसे में जनगणना 2027 को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सामाजिक संरचना का वास्तविक चित्र सामने ला सकती है।

साथियों, राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। कई राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण और सामाजिक गणना पहले ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। बिहार, कर्नाटक और अन्य राज्यों में किए गए जातीय सर्वेक्षणों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को और तेज किया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की दिशा में आगे बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भविष्य की नीतियां अधिक डेटा- आधारित और लक्ष्य केंद्रित होंगी। इससे यह भी संभावना बढ़ेगी कि सामाजिक योजनाओं में संसाधनों का वितरण वास्तविक जनसंख्या अनुपात और जरूरतों के आधार पर किया जा सके।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अप्रैल 2026 को भी ऐसी ही एक याचिका को खारिज किया था, जिसमें केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय अदालत ने याचिका में प्रयुक्त भाषा पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत का यह लगातार रुख स्पष्ट करता है कि वह जनगणना जैसे प्रशासनिक और नीतिगत विषयों में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहती है। इससे यह संदेश भी गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नीति निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचित सरकारों की होती है।जातिगत जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि भारत जैसे बहुस्तरीय सामाजिक ढांचे वाले देश में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं। यदि सरकार को यह ज्ञात ही नहीं होगा कि किस समुदाय की आबादी कितनी है, उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसी है, तो योजनाओं का सही लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अदालत ने भी सरकार की इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि पिछड़े वर्गों की संख्या और स्थिति जानना शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है।दूसरी ओर, विरोधियों की आशंका यह रही है कि जातिगत पहचान को फिर से केंद्र में लाने से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। उनका मानना है कि आधुनिक भारत को जाति से ऊपर उठकर आर्थिक और मानव विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार और अदालत दोनों ने यह स्पष्ट किया कि आंकड़े जुटाना और उनका दुरुपयोग करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी नीति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार है, तो केवल संभावित राजनीतिक उपयोग के आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। साथियों, जनगणना 2027 की डिजिटल प्रकृति भी इसे ऐतिहासिक बना रही है। पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इससे फर्जी या दोहराव वाले आंकड़ों को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की बड़ी परीक्षा भी होगी। (-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी)

वकीलों पर लाठी नहीं लोकतंत्र पर प्रहार

कांतिलाल मांडोत

लखनऊ जिला अदालत परिसर के बाहर जो कुछ हुआ वह केवल अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की एक गंभीर परीक्षा थी। अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ उसने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर दिया है। पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई केवल चैंबर तोड़ने तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने उस संवैधानिक गरिमा को भी आहत किया जिस पर भारतीय लोकतंत्र टिका हुआ है।

घटना की शुरुआत हाईकोर्ट के आदेश के पालन के नाम पर हुई। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर लेकर अदालत परिसर के बाहर पहुंची और कथित अवैध निर्माण हटाने लगी। जिन चैंबरों में वर्षों से वकील अपने पेशे का संचालन कर रहे थे उन्हें अचानक ढहाया जाने लगा। कई अधिवक्ताओं का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय और स्पष्ट सूचना तक नहीं दी गई। जिन लोगों ने जीवन के कई दशक अदालत परिसर में बिताए उनके सामने अचानक रोजी रोटी और सम्मान दोनों पर संकट खड़ा हो गया।

विरोध होना स्वाभाविक था। वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। कुछ सड़क पर बैठ गए। कुछ हाथ जोड़कर अपने चैंबर बचाने की गुहार लगाते रहे। लेकिन प्रशासन ने संवाद और समाधान का रास्ता चुनने के बजाय शक्ति प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदली और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जिस समाज में वकील संविधान और कानून के रक्षक माने जाते हैं उसी समाज में उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटना बेहद चिंताजनक दृश्य था।

सबसे दुखद पहलू यह रहा कि पुलिस की कार्रवाई में संवेदनशीलता लगभग दिखाई नहीं दी। एक अधिवक्ता ने आत्महत्या की धमकी दी। दूसरे अधिवक्ता रोते हुए कह रहे थे कि उनका चैंबर अवैध नहीं है और यदि उसे तोड़ा गया तो वे जीवित नहीं रहेंगे। इन आवाजों में केवल विरोध नहीं था बल्कि वर्षों की मेहनत और असुरक्षा का दर्द भी था। प्रशासन यदि चाहता तो बातचीत कर स्थिति संभाल सकता था। लेकिन जब राज्य की मशीनरी संवाद के स्थान पर डंडे को प्राथमिकता देती है तब हालात हिंसक बन जाते हैं। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या बुलडोजर अब प्रशासनिक कार्रवाई का स्थायी प्रतीक बन चुका है। कानून का शासन केवल कार्रवाई से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण प्रक्रिया से चलता है। यदि किसी निर्माण को अवैध माना गया था तो उसके लिए स्पष्ट नोटिस पुनर्वास और सम्मानजनक विकल्प देने चाहिए थे। अदालत परिसर में दशकों से बैठे अधिवक्ताओं को अचानक अपराधियों की तरह खदेड़ना किसी सभ्य व्यवस्था का संकेत नहीं हो सकता। घटना के दौरान पथराव भी हुआ जो निंदनीय है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं हो सकती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब प्रशासन संयम खो देता है तो भीड़ भी उग्र हो जाती है। पुलिस का दायित्व केवल बल प्रयोग करना नहीं बल्कि स्थिति को नियंत्रित रखना भी होता है। यदि पुलिसकर्मी स्वयं पत्थर उठाते दिखाई दें तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जनता पुलिस से निष्पक्षता और संयम की अपेक्षा करती है न कि प्रतिशोध की।

वकीलों पर लाठीचार्ज का असर केवल बार एसोसिएशन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आम जनता के न्यायिक विश्वास पर भी पड़ेगा। वकील अदालत और समाज के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि वही अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो न्याय व्यवस्था का वातावरण भी प्रभावित होगा। अदालत परिसर हमेशा गरिमा और संवाद का स्थान माना जाता रहा है। वहां हिंसा और टकराव लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को कमजोर करते हैं। यह भी विचारणीय है कि प्रशासनिक कार्रवाई में समानता दिखाई दी या नहीं। कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ अन्य निर्माणों को छोड़ दिया गया जबकि केवल चुनिंदा चैंबरों पर कार्रवाई हुई। यदि ऐसा है तो यह और गंभीर विषय है क्योंकि कानून की नजर में सब समान होने चाहिए। चयनात्मक कार्रवाई हमेशा अविश्वास और आक्रोश को जन्म देती है। सरकार और प्रशासन को समझना होगा कि कानून का पालन केवल शक्ति से नहीं कराया जा सकता। संवेदनशील मामलों में संवाद धैर्य और मानवीय दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होते हैं। अधिवक्ताओं के साथ बैठकर समाधान निकाला जा सकता था। पुनर्वास की स्पष्ट योजना बनाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरह बुलडोजर और पुलिस बल के सहारे कार्रवाई की गई उसने पूरे मामले को संघर्ष में बदल दिया। लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं होती। विरोध को सुनना और उसका सम्मान करना शासन की जिम्मेदारी है। यदि हर विरोध का उत्तर लाठी से दिया जाएगा तो समाज में भय और अविश्वास ही बढ़ेगा। पुलिस की भूमिका जनता की सुरक्षा करना है न कि उन्हें अपमानित करना। अदालत परिसर में हुई यह घटना प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण बन गई है। आज जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। यह तय होना चाहिए कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई। किसके आदेश पर बल प्रयोग हुआ। क्या वैकल्पिक उपाय संभव थे। साथ ही घायल अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों दोनों के प्रति संवेदना दिखाते हुए समाधान खोजा जाना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत संवाद में होती है दमन में नहीं।

लखनऊ की यह घटना केवल एक शहर का विवाद नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग ही सड़कों पर असुरक्षित महसूस करने लगें तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। कानून की रक्षा करने वालों के साथ कानूनसम्मत व्यवहार होना ही चाहिए। तभी जनता का विश्वास व्यवस्था में बना रहेगा।

प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को चुनौती''! मोदी सुनहरा अवसर चूक गये?

राजीव खण्डेलवाल

'' एक सवाल? जिसने भारत की वैश्विक छवि को फिर बहस में ला दिया।'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक नार्वे यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक नार्वे यात्रा थी। यह दौरा क्लीन एनर्जी, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्पेस सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत-नार्वे संबंधों को नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को नार्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट" से भी सम्मानित किया गया। यह उन्हें प्राप्त होने वाला 32वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। किन्तु राजनीति और कूटनीति में अक्सर कहा जाता है, "एक छोटी चूक, बड़ी उपलब्धियों पर भी परछाईं डाल देती है।" दुर्भाग्यवश, इस यात्रा के दौरान ऐसा ही एक प्रसंग विश्व व्यापी चर्चा का विषय बन गया। ''संयुक्त पत्रकार वार्ता, विदेशी दौरे के समापन की सामान्य क्रिया है।'' राजधानी ओस्लो में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता के समापन पर नार्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से जाते-जाते प्रश्न पूछा "प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ प्रश्न क्यों नहीं लेते?" प्रधानमंत्री बिना उत्तर दिये आगे बढ़ गये। इसके बाद भारतीय दूतावास की प्रेस ब्रीफिंग में उसी पत्रकार ने दूसरा तीखा प्रश्न किया। "जब हम साझेदारी मजबूत कर रहे हैं, तो हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके देश में मानवाधिकार उल्लंघन करें?" एक जानकारी के अनुसार भारत का इस मामले में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्रमशः 110 व 130 वा स्थान है। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सी.बी. जॉर्ज ने लगभग 13 मिनट तक इस पर विस्तृत उत्तर दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री स्वयं इसका छोटा, संयमित और आत्मविश्वास पूर्ण उत्तर नहीं दे सकते थे? वे सहजता से कह सकते थे। "भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जहां प्रेस की स्वतंत्रता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्थाएँ निरंतर कार्यरत हैं। आपका प्रश्न गलत तथ्यों पर आधारित है।" इतना भर कह देने से भारत का पक्ष कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से विश्व के सामने आता। ''प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या बला है?'' चूंकि नॉर्वे (जहां प्रधानमंत्री अभी दौरे पर गए) इसका सिरमौर बना हुआ है इसलिए इसकी चर्चा अभी ज्यादा है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ष 2002 से ''विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक'' को प्रकाशित कर रही है। विश्व के 180 देशों में नार्वे लगातार प्रथम

स्थान पर बना हुआ है, जबकि भारत वर्ष 2026 की सूची में 157 वें स्थान पर है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भारत से ऊपर पाकिस्तान (152 वे) और बांग्लादेश (153 वे) जैसे देश हैं। हालांकि भारत सरकार और अनेक विशेषज्ञ समय-समय पर इस सूचकांक की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2020 में संसद में कहा था कि यह रैंकिंग सीमित सैंपल, गैर-पारदर्शी प्रक्रिया और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण (Biased)पर आधारित है। इन तरीकों में कुछ दम भी दिखाई देता है। फिर भी, विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता मापने के लिए यह सूचकांक सबसे अधिक उद्धृत किया जाता है। ''मीडिया का मूल धर्म-सवाल पूछना?'' : पत्रकारिता का मूल प्राथमिक दायित्व ''सत्ता'' से सवाल पूछना है। नार्वे की डीएक्सबी सेन दैनिक समाचार पत्र की अपरिचित महिला पत्रकार Helen Eggen द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया प्रश्न इसी लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा था। किंतु भारत के सोशल मीडिया के एक वर्ग और मेनस्ट्रीम मीडिया चैनलों ने जिस प्रकार उस महिला पत्रकार को ट्रोल किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण होकर आत्मघाती भी है। दरअसल, यह घटना भारतीय मीडिया के लिए आत्ममंथन का अवसर थी। लेकिन कुछ कट्टर समर्थक मेनस्ट्रीम मीडिया की ओछी प्रतिक्रिया ने अनजाने में भारत के 157वें स्थान की पुष्टि कर दी, जिनका भारत खंडन करना चाहता है। ''लोकतंत्र का चौथा स्तंभ! मीडिया।'': विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जबकि अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा पैमाना प्रेस की स्वतंत्रता है। दोनों का चोली-दामन का साथ है। परंतु विडंबना देखिए! प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अमेरिका भी 80वें स्थान पर है।यह कहना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण केवल वर्ष 2014 के बाद बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि समस्या पुरानी है। वर्ष 2002 में भारत 80 वें स्थान पर था (139 देशों में) नीचे से 59वां। वर्ष 2008 में 118 वें स्थान पर पहुँच गया (173 देशों में) नीचे से 55वां। वर्ष 2014 में 140 वें स्थान पर था (180 देशों में) नीचे से 40वां। और अब 157 वें स्थान पर पहुँच चुका है (180 देशों में) नीचे से 23वां। मतलब लगातार भारत निम्न से निम्नतर स्तर पर जा रहा है। स्पष्ट है कि सत्ता कोई भी रही हो, प्रेस और सरकार के संबंध कभी पूर्णतः सहज नहीं रहे। आपातकाल आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रेस को लेकर "काले अध्याय" के रूप में याद किया जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी लोकतंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास होता है, सबसे पहला प्रहार ''प्रेस की स्वतंत्रता'' पर ही होता है। इसलिए भारतीय प्रेस व सरकार दोनों को इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा प्रेस मजबूत बना रहा है, ताकि लोकतंत्र लड़खड़ाए नहीं। "सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस" से परहेज क्यों?: प्रधानमंत्री मोदी अब तक 6 महाद्वीपों के 80 देशों की 100 विदेश यात्राएँ कर चुके हैं। अधिकांश दौरों में संयुक्त बयान जारी हुए, लेकिन स्वतंत्र प्रेस वार्ताओं से सामान्यतः दूरी बनाकर बचते ही रहे। वर्ष 2023 में अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन और वर्ष 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस वार्ताओं में सीमित प्रश्न (2+2=4) लिये गये, लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई स्वतंत्र "सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस" नहीं की है। ''सेंचुरी'' विदेश यात्रा में मोदी को ''छक्का'' मारने की आवश्यकता थी, जिसका अवसर उन्हें मिला था। दुर्भाग्यवश यह अवसर उन्होंने बाल खो दिया। आप कह सकते है नो बॉल आ वाईड बॉल फेंकी गई थी। ''एक अवसर जो हाथ से निकल गया''। राजनीति में कई बार "मौन भी संदेश बन जाता है।" नार्वे की इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह संदेश गया कि भारत में पत्रकारों के कठिन प्रश्नों से बचा जाता है। विडंबना यह रही कि जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भारत "अर्धसत्य","पक्षपातपूर्ण" व द्विवेश पूर्ण बताता है, उसी धारणा को यह प्रसंग और बल देता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बुद्धिमता पूर्ण उत्तर व वाकपटुता से न केवल आलोचनाओं का प्रभाव कम कर सकते थे, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते थे। इसलिए यह केवल एक ''प्रोटोकॉल'' संबंधित चूक नहीं थी, बल्कि राजनयिक कूटनीतिक त्रुटि भी थी।

आज का राशिफल

मेष राशि : मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आप अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। मित्र और सहकर्मी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। बहुत दिनों के पेंडिंग काम आज पूरे कर लेंगे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिये कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे।

वृष राशिः वृष राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्यार रिश्ते को और भी बेहतर बनायेंगे। आपका सामाजिक जीवन आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। आज कारोबार में व्यस्तता और दौड़ भाग से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे।

मिथुन राशिः मिथुन राशि वालों आज आपको तरक्की के कुछ नये साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस में स्थिति सामान्य रहेगी। कपड़ों के कारोबारियों को दोगुना मुनाफा होगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन ताजगी भरा रहेगा। किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे।

कर्क राशिः कर्क राशि वालों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नये रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशिः सिंह राशि वालों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा फायदा दिलायेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसानों को सरकार की ओर से कुछ नई योजनाओं का लाभ मिलेगा।

कन्या राशिः कन्या राशि वालों आज आपका दिन शानदार रहेगा। बचपन के किसी दोस्त का आज फोन आ सकता है। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। आपके अधूरे काम पूरे हो जायेंगे। बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण नए एग्रीमेंट हो सकते हैं और इसे बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। आज आपकी मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण लोगों से होगी।

तुला राशिः तुला राशि वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको नया काम मिल सकता है, जिसमें आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। आज के दिन की जाने वाली आपकी यात्राएं फलीभूत होंगी। आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ सैर सपाटे की योजनाएं भी बना सकते हैं।

वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशि वालों आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिल सकती है। आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। ऑफिस के काम से किसी सहकर्मी के साथ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर बनवा रहे लोगों का काम आगे बढ़ेगा।

धनु राशिः धनु राशि वालों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा सुनहरा मौका मिलेगा।

मकर राशिः मकर राशि वालों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आयेगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होंगे।

कुंभ राशिः कुंभ राशि वालों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जायेंगे। आज कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिये फायदेमंद साबित होगी।

मीन राशिः मीन राशि वालों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जायेंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आयेगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

प्रकाशक एवं स्वामी सागर सूरज, द्वारा सरोतर निवास, राजाबाजार-कचहरी रोड, मोतिहारी, बिहार-845401 से प्रकाशित व प्रकाश प्रेस मोतिहारी से मुद्रित, संपादक-सागर सूरज* फोन न.9470050309 प्रसारः-9931408109 ईमेलः-bordernewsmirror@gmail.com वेबसाइटः-bordernewsmirror.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार) RNI. N. BIHBIL/2022/88070

शुभमन ने तीसरी बार आईपीएल में 600 से अधिक रनों के साथ बनाया रिकार्ड

एजेंसी, अहमदाबाद

गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ने आईपीएल के इस सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 600 से अधिक रन बनाये हैं। इस प्रकार वह तीन बार इस टूर्नामेंट में ये अहम उपलब्धि हासिल करने वाले कप्तानों की सूची में नंबर एक पर पहुंच गये हैं। शुभमन ने अपने करियर में तीसरी बार और कप्तान के रूप में दूसरी बार यह 600 से अधिक रन किसी एक सत्र में बनाये। इसी के साथ ही शुभमन आईपीएल इतिहास में चौथे ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने एक सत्र में 600 से ज्यादा रन बनाये हैं। इससे पहले विराट ने 2025 सत्र में 600 से अधिक रन बनाये थे। वहीं शुभमन ने करियर में तीसरी बार 600 से अधिक रन बनाये हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में 890 रन बनाए थे, जो एक सत्र में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाये दूसरे सबसे ज्यादा रन है। इस शानदार उपलब्धि के साथ ही शुभमन कप्तान के रूप में एक से अधिक बार 600 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरीसबी) के विराट कोहली ने साल 2013 में एक बार उपलब्धि हासिल की थी। तब कोहली भी सबसे कम उम्र में एक से अधिक बार 600 से अधिक रन सीजन बनाने वाले खिलाड़ी थे। दिग्गज कोहली ने साल 2016 में अपने करियर में दूसरी बार 600 रन से अधिक बनाये थे। वहीं डेविड वॉर्नर एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार सत्र में कप्तान रहते हुए 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।

सीएसके को दोहरा झटका, आईपीएल से बाहर हुई, रुतुराज पर 24 लाख का जुर्माना

एजेंसी, अहमदाबाद

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में गुजरात टाइटंस टीम के खिलाफ हार के साथ ही दोहरा झटका लगा है। इस हार के साथ ही सीएसके जहां प्लेऑफ से बाहर हो गयी। वहीं धीमे ओवर रेट के लिए रुतुराज पर जुर्माना लगा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए सीएसके टीम को इस लीग मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हर हाल में जीत की जरूरत थी पर वह असफल रही। इस मैच में टीम को धीमी ओवर गति के लिए जिम्मेदार माना गया। जिसके कारण रुतुराज पर मोटा जुर्माना भी लगा है। यह इस सत्र में दूसरी बार था जब रुतुराज गायकवाड़ की टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाई। ये दूसरी बार है जब वह धीमी ओवर गति के लिए फंसी है। इससे पहले 18वें मैच में भी सीएसके को धीमी ओवर गति का दोषी पाया गया था। आईपीएल के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर गति से जुड़े अपराधों को कवर करता है, गायकवाड़ पर 24 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। कप्तान के अलावा, प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर भी शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों पर छह लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 फीसदी, जो भी कम हो, का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद सीएसके की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह लड़खड़ा गई और सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई। इस प्रकार उसे 89 रनों की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी।

हार्दिक पांड्या को मुम्बई इंडियंस से रिलीज करने की मांग उठी

एजेंसी, मुम्बई

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुम्बई इंडियंस का प्रदर्शन आईपीएल में लगातार तीसरे सत्र में भी बेहद खराब रहा है और टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पायी है। ऐसे में पांड्या को टीम से रिलीज करने की मांग एक बार फिर तेज हो गयी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पहले ही सत्र में खिताब जीता था और दूसरे सत्र में वह उपविजेता रही थी। जिसके बाद वह मुम्बई आये थे और रोहित शर्मा की जगह पर उन्हें कप्तान बनाया गया लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। टीम के प्रदर्शन के अलावा उनका स्वयं का प्रदर्शन भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। मुंबई इंडियंस पिछले तीन सत्र में केवल एक बार ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाई है, जबकि दो बार तालिका में सबसे नीचे रही है, जिसमें आईपीएल 2024 भी शामिल है। इसी वजह से अब पांड्या से सिर्फ कप्तानी छीनने की नहीं, बल्कि उन्हें टीम से ही रिलीज़ करने की मांग उठ रही है। इसी को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अपनी राय रखते हुए एक बड़ा सुझाव दिया है। हार्दिक को लेकर वॉन ने कहा, रिलीज़ कर दो। हालांकि, उन्होंने तुरंत एक और विकल्प सुझाया। उन्होंने कहा, उसे कैमरून ग्रीन से रिप्लेस कर दो। वॉन का यह सुझाव कई क्रिकेट जानकारों को काफी पसंद आ रहा है। पांड्या और ग्रीन दोनों एक ही तरह के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ऐसे में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच एक ट्रेड डील की संभावना बन सकती है। इस संभावित अदला-बदली से दोनों ही टीमों को लाभ हो सकता है।

विनेश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को लगायी फटकार

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को ट्रायल के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के फैसले को लेकर उसे कड़ी फटकार लगायी है। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विनेश के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश मैटरनिटी ब्रेक के बाद खेल में वापसी कर रही है। वहीं डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ट्रायल के लिए आयोग्य घोषित करते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उन पर नुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई ने विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून, 2026 तक रोक लगा दी थी। डब्ल्यूएफआई के इस फैसले के कारण से विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले सकी थीं। विनेश ट्रायल की अनुमति मांगने के लिए डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। डब्ल्यूएफआई ने विनेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ट्रायल में शामिल होने की अपील यह कहकर ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

नेमार फिर चोटिल हुए, विश्वकप में खेलने पर संशय छाया

एजेंसी, यो डी जनेरियो

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार एक बार फिर चोटिल हो गये हैं। ऐसे में अगले माह होने वाले फीफा विश्वकप में उनके खेलने को लेकर एक बार फिर संशय छा गया है। नेमार लंबे समय के बाद हाल ही में मैदान पर लौटे थे जिसके बाद उन्हें विश्वकप के लिए टीम में भी शामिल किया गया था पर अब उनके चोटिल होने से प्रशंसकों में निराशा का भाव है। इसका कारण है कि अब विश्वकप में एक माह से भी कम समय है। 34 साल के नेमार सैंटोस आजकर अपने क्लब की ओर से खेलकर फिटनेस हासिल करने में लगे थे पर सैन लोरेंजो के खिलाफ अपनी टीम के घरेलू कोपा सुदामेरिकाना मैच में वह नहीं उतरे। इसका कारण उनकी पिंडली में लगी चोट को बताया गया है हालांकि क्लब का कहना है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है और चिंता की जरुरत नहीं है। सैंटोस टीम के डॉक्टर रोड्रिगो ज़ोगैब ने उम्मीद जतायी है कि नेमार 27 मई को ब्राजील के विश्व कप से पहले होने वाले पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए फिट हो जायेंगे। जोगैब ने कहा, नेमार नेशनल टीम में पूरी तरह फिट या लगभग फिट होकर शामिल होंगे। इस बात की भी संभावना है कि वह अगले मंगलवार को डेपोटिर्वो कुएन्का के खिलाफ खेल सकते हैं। गौरतब है कि नेमार ब्राजील के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेमार ने 128 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 79 गोल दागे हैं।

बिजनेस

घरेलू सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

एजेंसी, नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में तेजी का दौर जारी है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 कैरेट सोना आज 1,60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,61,680 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोना आज 1,46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,48,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह चमकीली धातु चांदी दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,85,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,60,240 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,760 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,60,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,61,680 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,48,110 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,46,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

मारुति अगले माह कार के दाम में 30 हजार रुपये तक की करेगी बढ़ोतरी

एजेंसी, नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने कार की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में अगले माह 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी नियामकीय सूचना में बताया कि उसने अपने पूरे मॉडल पोर्टफोलियो में वाहनों की कीमतों में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति और लागत में बढ़ोतरी के कारण जून से लागू होंगी। कंपनी ने कहा कि अलग-अलग मॉडल्स के हिसाब से कीमतों में बदलाव अलग रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय बाजार में मारुति की पॉपुलर कारों में डिजायर, अर्टिगा, स्विफ्ट, ब्रेजा, बलेनो और फ्रॉन्क्स के साथ ही विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, ऑल्टो के10, इनविक्टो समेत अन्य मॉडल शामिल है।

स्विगी को एओए में बदलाव के लिए नहीं मिली जरूरी शेयरधारक मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

खाद्य एवं पेय सामग्री की आपूर्ति करने वाली ऑनलाइन कंपनी स्विगी को अपने कंपनी गठन के कायदे-कानून में बदलाव के लिए आवश्यक शेयरधारक मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके जरिये वह खुद को भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रित कंपनी (आईओसीसी) के रूप में योग्य बनाना चाहती थी।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी गठन के कायदे-कानून (एओए) में संशोधन के प्रस्ताव को 72.35 फीसदी शेयरधारकों का समर्थन मिला है, जो आवश्यक सीमा से 2.65 फीसदी कम रहा। कंपनी ने इसके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया अपनाई थी। इसमें एओए में बदलाव करने और रेनन डी कास्त्रो आल्वेस पिंटो को गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मांगी गई थी।

विशेष प्रस्ताव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्विगी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि स्विगी प्रस्ताव के परिणाम को स्वीकार करती है, जिसे 72.35 फीसदी शेयरधारकों की मंजूरी मिली, जो आवश्यक सीमा से 2.65 फीसदी कम है। हालांकि, इसके नियुक्ति का प्रस्ताव 98.98 फीसदी बहुमत के साथ पारित हो गया। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ संवाद को जारी रखेगी और सकारात्मक परिणाम की दिशा में अपना काम करेगी। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नियमों के तहत वर्तमान में किसी कंपनी को भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रित तभी माना जाता है, जब उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय नागरिकों या पात्र भारतीय संस्थाओं के पास हो। इसमें निदेशक मंडल की संरचना और नामांकन व्यवस्था के जरिये घरेलू नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 325 अंक उछला

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी संकट पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति के इंतजार के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी बना हुआ है। सेंसेक्स में 325 अंक की बढ़त और निफ्टी भी 90 अंकों की तेजी है। कारोबार की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 324.95 अंक यानी 0.43 फीसदी उछलकर 75,508.31 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 96.10 अंक यानी 0.41 फीसदी की तेजी के साथ 23,750.80 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। आज के कारोबार में बैंक और रियल्टी शेयरों में खरीदारी है। वहीं, शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे बढ़कर 96.30 पर पहुंच गया है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है निवेशक भी अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति का इंतजार कर रहे है। उल्लेखनीय है कि पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को सेंसेक्स 135.03 अंक यानी 0.18 फीसदी टूटकर 75,183.36 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 4.30 अंकों यानी 0.018 फीसदी की गिरावट के साथ 23,654.70 के स्तर पर बंद हुआ था।

डीआरआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 हजार किलो विदेशी सुपारी जब्त की, पांच गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली । राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस हफ्ते की शुरुआत में संचालित किए गए दो बड़े अभियानों में लगभग 60 हजार किलोग्राम तस्करी की गई विदेशी सुपारी जब्त की है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि इस विदेशी सूखी सुपारी की म्यांमा-मिजोरम सीमा के रास्ते म्यांमा से भारत में तस्करी की जा रही थी। डीआरआई ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मिजोरम और असम में अभियान संचालित करते हुए ये ज़ब्ती की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान में डीआरआई को असम राइफल्स की 38वीं बटालियन का सहयोग मिला। अब तक इन अभियानों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश से सुपारी की अवैध आवक घरेलू सुपारी उत्पादकों को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर रही है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ओएफएस खुला

एजेंसी, नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की चार फीसदी हिस्सेदारी के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) 31 रुपये प्रति शेयर की दर से शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गई । खुदरा निवेशक सोमवार को इस शेयर बिक्री के लिए बोली लगा सकेंगे। सेंट्रल बैंक का यह 31 रुपये प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर गुरुवार को इसके शेयर के 33.91 रुपये के बंद भाव से 8.58 फीसदी कम है। बीएसई पर इस बैंक के शेयर आज 32.06 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। यह पिछले दिन के बंद भाव से 5.46 फीसदी कम है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस बिक्री पेशकश में अतिरिक्त चार फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीनशू विकल्प भी शामिल है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आठ फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से केंद्र को 2,456 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह बिक्री पेशकश सरकार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी मानक को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। सेबी के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी तक सार्वजनिक हिस्सेदारी होना अनिवार्य है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार के पास वर्तमान में 89.27 फीसदी हिस्सेदारी है। यदि सरकार ग्रीनशू विकल्प का उपयोग करती है तो बैंक में उसकी हिस्सेदारी घटकर 81.27 फीसदी रह जाएगी। उललेखनीय है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिक्री पेशकश के जरिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2,624 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,419 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है।

मौनी रॉय ने बैकलेस आउटफिट में लूटी महफिल

300 घंटे में तैयार हुई ये खूबसूरत ड्रेस

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस मौनी रॉय लगातार अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं. अब एक्ट्रेस का दूसरा लुक सामने आ चुका है, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा एलिगेंट और स्टनिंग नजर आ रही हैं. इस बार मौनी रॉय ने ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत बैकलेस गाउन पहना. इस ड्रेस को बनाने में करीब 300 घंटे लगे हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

टीवी की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत बैकलेस गाउन पहनकर उतरीं, जिसकी फिटेड सिल्हूट उनके लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रही है. इस आउटफिट के साथ जुड़ा लंबा फ्लोई ट्रेल उनके लुक को रॉयल और स्टाइलिश टच दे रहा है. मौनी ने बताया कि उनकी इस ड्रेस को बनाने में करीब 300 घंटे लगे हैं. मौनी ने अपने बालों को सॉफ्ट वेवी लुक में ओपन रखा है. साइड से पार्टिंग के साथ उनके ब्राउन टोन बाल चेहरे पर काफी नैचुरल और फ्रेश लग रहे हैं. मौनी ने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. ड्यूई बेस, सॉफ्ट पिंक ब्लश और न्यूड-पिंक लिप शेड ने उनके चेहरे पर नैचुरल ग्लो दिया. इस लुक में मौनी का एलीगेंट और ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. मौनी की इस ड्रेस को पूजा शाह ने डिजाइन किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर और टीजर कान्स में लॉन्च हो चुका है, जिसकी तस्वीरें वो जल्द शेयर करेंगी. मौनी का ये रॉयल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ नजर आ रहा है. बता दें कि मौनी रॉय पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादी के चार साल बाद अपने पति सूरज नांबियार से अलग हो गई हैं. हाल ही में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो मौनी जल्द ही फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगी. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास विश्वंभरा और द वाइव्स जैसी फिल्में भी हैं.

'गुल्लक 5 का ऐलान हुआ, शो में अनंत वी. जोशी की एंट्री, अन्नू मिश्रा के किरदार में आएंगे नजर

द वायरल फीवर (टीवीएफ) ने अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज गुल्लक के 5वें सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। निर्माताओं ने सीरीज का टीजर जारी किया है, जिसने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है। टीजर में अन्नू भइया उर्फ अन्नू मिश्रा का किरदार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, जिसे अनंत वी जोशी निभा रहे हैं। दरअसल, पिछले 4 सीजन से इस किरदार को वैभव राज गुप्ता निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। सोनी लिव ने गुल्लक सीजन 5 का टीजर जारी करते हुए लिखा, वही रंगत, वही आदतें, वही शरारतें..अब पहचान तो हो गई इनकी! हमारे अन्नू मिश्रा फिर आ रहे हैं नए किस्से लेकर, अपने प्यारे मिश्रा परिवार के साथ। बता दें, अनंत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय (2025) से लोकप्रियता मिली थी। वहीं जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी और हर्ष मयार अपने किरदार में वापसी करेंगे। गुल्लक 5 की रिलीज तारीख का आना बाकी है। जहां गुल्लक के पिछले चारों सीजनों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला, वहीं इसके पांचवें सीजन का इंतजार अपने चरम पर था. अब, यह इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है और कैप्शन में लिखा है - ऐसा लग रहा है... मिश्रा निवास में कुछ बदल गया है... आपको भी समझ आ रहा है क्या? 'गुल्लक भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पसंदीदा ओटीटी शोज में से एक है.अपनी शानदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है.वहीं, नए सीजन में परिवार की पुरानी मिठास के साथ नई कहानियां और मोड़ देखने को मिलेंगे.

फिल्म पति पत्नी और वो दो की बढ़ी कमाई

हाथ मलती रह गई आखिरी सवाल

आयुष्मान खुराना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसे सितारे भी मौजूद हैं। वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद यह कारोबारी दिनों में लौट आई है और 5वें दिन आंकड़ों में बढ़त भी देखी गई। दूसरी ओर, फिल्म आखिरी सवाल पहले ही हफ्ते में अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर चुकी है। सैकनिल्क के मुताबिक, पति पत्नी और वो दो ने 5वें दिन 3.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह कलेक्शन चौथे दिन हुई कमाई 3.25 करोड़ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक कुल 24.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। देखा जाए तो आयुष्मान अपने जाल में दर्शकों को फंसाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हालांकि, फिल्म का कथित बजट लगभग 65 करोड़ वसूलने के लिए अभी राह लंबी होगी। संजय दत्त की फिल्म एक दिन पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। 5वें दिन भी इसने 23 लाख रुपये कमाए और अब तक कुल 2.43 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है। हाल ही में दर्शकों को एक पर एक टिकट फ्री वाला प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसका भी फायदा होते नहीं दिखा है। उधर सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म करप्पू ने 5वें दिन 12.75 करोड़ के साथ कुल 95.05 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

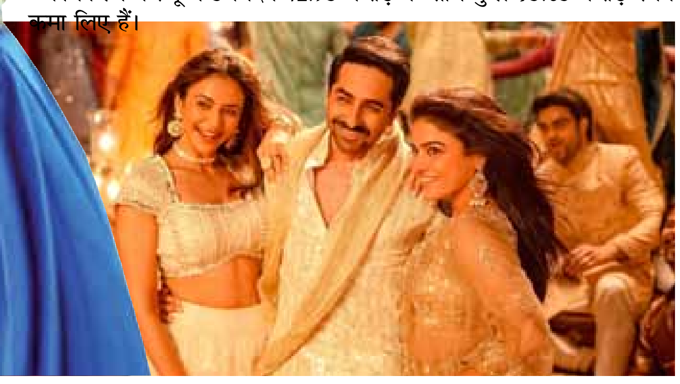

दो महीने बाद भी कोहराम मचा रही है धुरंधर 2

बस 1.3 करोड़ और कमाते ही दुनियाभर में रच देगी इतिहास

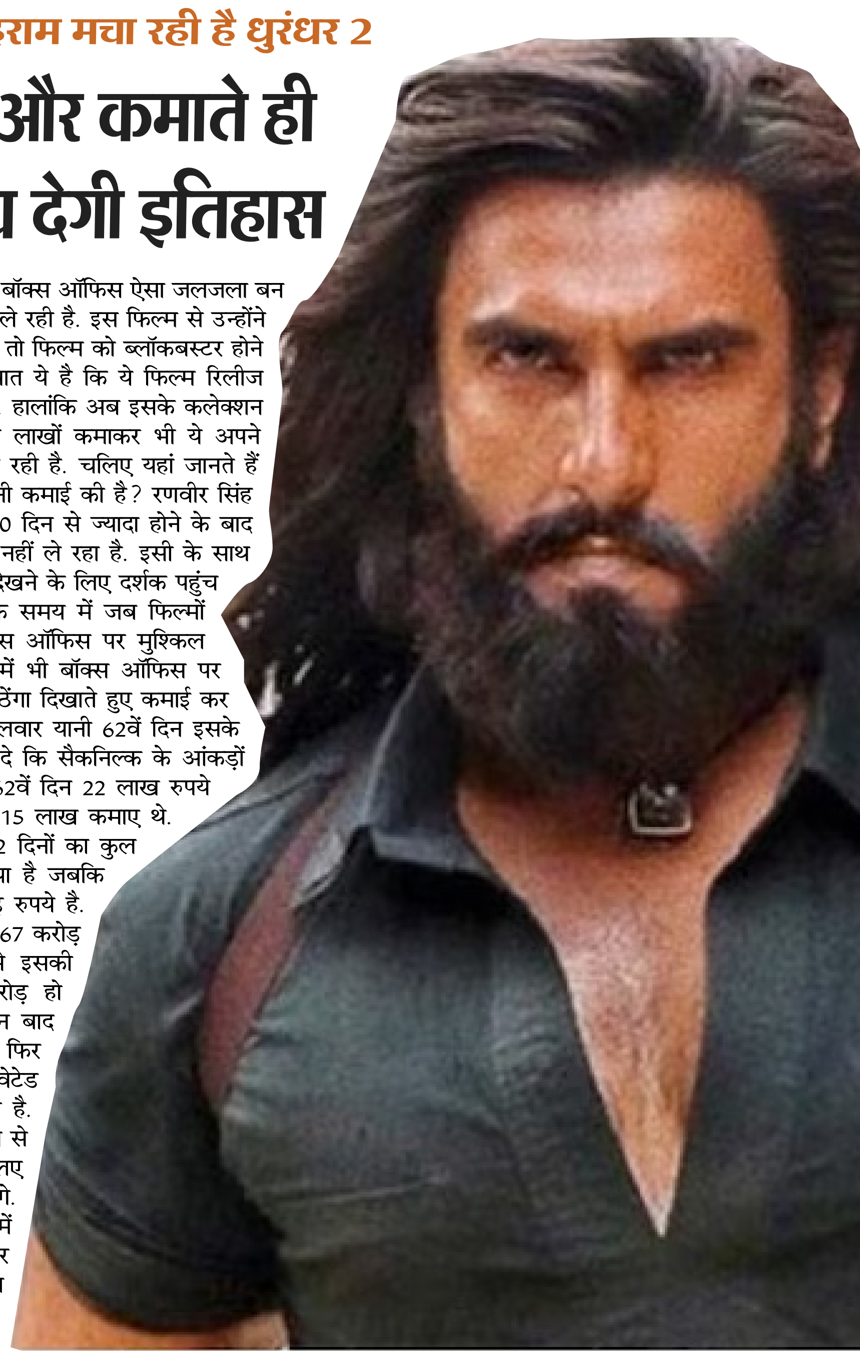

आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस ऐसा जलजला बन गई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया है कि कंटेंट में दम हो तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के दो महीने बाद भी कमाई कर रही है. हालांकि अब इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आ चुकी है लेकिन लाखों कमाकर भी ये अपने कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा कर रही है. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर 2 ने रिलीज के 62वें दिन कितनी कमाई की है? रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 का क्रेज रिलीज के 60 दिन से ज्यादा होने के बाद भी दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. इसी के साथ इस फिल्म को अब भी सिनेमाघरों में देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं. हैरानी की बात ये कि आज के समय में जब फिल्मों के एक दो हफ्ते तक टिकना भी बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल होता है तो वहीं ये फिल्म नौंवे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है और तमाम नई फिल्मों के ठेंगा दिखाते हुए कमाई कर रही है.. दिलचस्प बात ये है नौंवे मंगलवार यानी 62वें दिन इसके कलेक्शन में तेजी भी देखी गई. बता दे कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर 2 ने 408 शो में 62वें दिन 22 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं 61वें दिन इसने महज 15 लाख कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म का भारत में 62 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 1146.35 करोड़ हो गया है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1371.95 करोड़ रुपये है. वहीं ओवरसीज में फिल्म ने कुल 426.67 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड कमाई अब 1798.62 करोड़ हो चुकी है. धुरंधर 2 का जलवा 62 दिन बाद भी बरकरार है. वहीं अब ये वर्लडवाइड फिर से अपनी रिकॉर्ड बुक में एक मच अवेटेड उपलब्धि दर्ज करने की ओर बढ़ रही है. दरअसल ये फिल्म 18 सौ करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. इस आंकड़े को छूने के लिए फिल्म के 1.3 करोड़ और कमाने होंगे. अगर दसवें वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो ये इस आंकड़े के छूकर इतिहास रच सकती है. देखने वाली बात होगी कि धुरंधर 2 ये मील का पत्थर पार कर पाती है या नहीं.

बॉयफ्रेंड शिखर ने जाह्नवी कपूर को बताया रियल और रील लाइफ डॉन

हाल ही में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म के ट्रेलर में जाह्नवी कपूर के नए अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है। ट्रेलर देखने के बाद जान्हवी के बॉयफ्रेंड माने जा रहे शिखर पहाड़िया ने भी अभिनेत्री की खुलकर सराहना की है। शिखर पहाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'पेड्डी' का ट्रेलर साझा करते हुए जाह्नवी कपूर को "रियल और रील लाइफ की लेडी डॉन" बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जाह्नवी कपूर असल जिंदगी और फिल्मों दोनों में बेहद दमदार हैं। साथ ही उन्होंने अभिनेता राम चरण की भी तारीफ करते हुए कहा कि दोनों की जोड़ी शानदार लग रही है और वह फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिखर की इस पोस्ट पर जाह्नवी कपूर ने भी प्यार भरा रिएक्शन दिया। अभिनेत्री ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए कई हार्ट इमोजी साझा किए। सोशल मीडिया पर दोनों का यह प्यारा संवाद अब तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि दोनों ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें कई बार साथ देखा जा चुका है। दोनों अक्सर छुट्टियों, मंदिर दर्शन और पारिवारिक कार्यक्रमों में एक साथ नजर आते हैं। शिखर पहाड़िया को जाह्नवी कपूर के परिवार के साथ भी कई खास मौकों पर देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने कई साल पहले एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। बीच में कुछ समय के लिए दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन बाद में दोनों फिर करीब आ गए। वहीं फिल्म 'पेड्डी' की बात करें तो यह एक पैन-इंडिया स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है। फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। राम चरण इसमें एक ऐसे खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं, जो पेशेवर खिलाड़ी नहीं बल्कि गली क्रिकेटर और पहलवान है, जो जिंदगी की तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। फिल्म में 'मिर्जापुर' से लोकप्रिय हुए दिव्येंदु शर्मा, शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

गर्मियों के लिए परफेक्ट हैं ये 5 फेस मिस्ट, जानिए बनाने का तरीका

गर्मी के कारण त्वचा पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में त्वचा को ठंडक देने के लिए आप बाजार से फेस मिस्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उनमें मौजूद अप्राकृतिक रंग और खुशबू त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मिस्ट बनाने का तरीका बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आपकी त्वचा को ठंडक और नमी मिलेगी। खीरे का फेस मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में खीरे को अच्छे से पीसें, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। जब भी आपको लगे कि गर्मी से आपकी त्वचा काफी बेजान हो गई है, तो उस पर खीरे के फेस मिस्ट का छिड़काव करें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ उसे ठंडक भी देगा। खीरे के इस फेस मिस्ट से आपकी त्वचा को ताजगी मिलेगी। गुलाब जल और नींबू का फेस मिस्ट न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसे नमी भी देता है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे गुलाब जल के साथ नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को ठंडक देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। गुलाब जल और नींबू का यह मिस्ट आपकी त्वचा को तरोताजा बनाए रखेगा। एलोवेरा और खीरे का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे नमी भी देता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे एलोवेरा जेल के साथ खीरे का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। एलोवेरा और खीरे का यह मिस्ट आपकी त्वचा को नमी देगा। पुदीना और नारियल पानी का फेस मिस्ट पुदीना और गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें मौजूद पुदीने की ताजगी और नारियल पानी की ठंडक आपकी त्वचा को तरोताजा रखती है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे पुदीने के पत्ते डालें, फिर उसमें नारियल पानी डालकर अच्छे से हिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे नमी भी देगा। गुड़हल फूल का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल फूल की पंखुड़ियों को पानी में उबालें, फिर इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इसे अपने चेहरे पर छिड़कें। इन फेस मिस्ट के इस्तेमाल से आप गर्मियों में तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी त्वचा भी खिली-खिली रहेगी।

भारत में अपने ही कलाकारों को सबसे ज्यादा करते है ट्रोलः अमीषा पटेल

सामाजिक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर खुलकर राय रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रोलिंग कल्चर और फर्जी पीआर गेम को निशाने पर लिया है। उन्होंने भारतीय मानसिकता को "दुखद" और "शर्मनाक" बताते हुए कहा कि भारत में कलाकारों को सबसे ज्यादा ट्रोल उनके अपने ही लोग करते हैं, जबकि हॉलीवुड सितारों को उनके देश में इतना विरोध नहीं झेलना पड़ता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए अमीषा पटेल ने कहा कि आजकल लोगों की मानसिकता दूसरों को नीचे गिराने और नकारात्मकता फैलाने वाली हो गई है। उन्होंने बड़े कार्यक्रमों और इवेंट्स में सितारों के कपड़ों, लुक और स्टाइल को लेकर होने वाली आलोचनाओं पर नाराजगी जताई। अमीषा के मुताबिक, यह सिर्फ दुखद ही नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक भी है कि भारतीय दर्शक अपने ही कलाकारों के प्रति इतनी कठोर सोच रखते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में एक्टर्स को अपने ही देश में हॉलीवुड सितारों की तुलना में कहीं ज्यादा ट्रोल किया जाता है। अभिनेत्री ने सिर्फ ट्रोलिंग कल्चर ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते पीआर गेम पर भी खुलकर हमला बोला। हाल ही में मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि आजकल कई कलाकार खुद को नंबर वन स्टार साबित करने में लगे हैं, चाहे उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो या नहीं। अमीषा ने कहा कि कुछ युवा कलाकार अपनी पीआर टीमों के जरिए खुद को सुपरस्टार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली पहचान दर्शकों के प्यार और फिल्मों की सफलता से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन कलाकारों ने अभी तक 200 करोड़ क्लब की कोई फिल्म नहीं दी, वे भी खुद को नंबर वन बताने में लगे हैं। अमीषा ने कहा कि किसी कलाकार को तभी सुपरस्टार कहा जाना चाहिए जब उसने ऐसा काम किया हो जो इतिहास बना दे। उन्होंने फर्जी प्रचार और पीआर के खेल को बंद करने की सलाह देते हुए इसे "कड़वी सच्चाई" बताया। अपनी बात को मजबूती देने के लिए अमीषा ने अपनी फिल्मों का भी जिक्र किया।

'Democracies need outlets for dissent': Shashi Tharoor backs Cockroach Janta Party after X account withheld

New Delhi, Agency: Congress MP Shashi Tharoor came out in support of the satirical Cockroach Janta Party (CJP), questioning the withholding of its X account and calling it "disastrous and deeply unwise."

"I'm incredibly intrigued by the rise of #CockroachJantaParty, which has already reached more than 15 million (now over 19 million) followers on Instagram in just five days," Tharoor posted on X.

The CJP's X account, which had over two lakh followers, was withheld in India following a legal demand on Wednesday. Founder Abhijeet Dipke confirmed the suspension, writing: "As expected Cockroach Janta Party's account has been withheld in India." Within hours, the group launched a new account titled "Cockroach is Back," posting: "You thought you could get rid of us? Lol."Tharoor said he understood the frustrations of the youth and saw why they were resonating with the satirical movement.

"This is precisely why the account being withheld on X is disastrous and deeply unwise - there should be an outlet for the youth to express their feelings and so, let CJP's

account function instead of shutting it down!" he wrote.

"Democracies need outlets for dissent, humour, satire and even frustration," he added.

While Tharoor said he was uncertain about the future of the movement, he hoped that the youngsters behind it would find a way to bring their energy into mainstream politics.

"This is an opportunity that the Opposition must seize," the Congress MP wrote, suggesting that political parties take note of the viral trend and work on bringing the youth towards them.

Congress leader Deepender Singh Hooda also called the withholding of the CJP's X account a "cockroach ban," saying it was "completely inappropriate in a democracy." He added that the movement reflects the deep-seated anger among the youth against a "flawed system" created by the BJP.

The CJP emerged earlier this month after Chief Justice of India Surya Kant's controversial remarks during a court hearing, in which he reportedly compared some unemployed youth to "cockroaches" and "parasites." The CJI later issued a clarification, saying his comments were aimed at people using "fake and bogus degrees" and that reports claiming he insulted India's youth were "totally baseless."

But by then, the Cockroach Janta Party had already turned the controversy into an internet movement, garnering over 19.5 million followers on Instagram.

The satirical outfit describes itself as "a political party for the lazy, the unemployed, and the chronically correct," with its headquarters "wherever the wifi works."

Political banter finds its way into legal arguments in SC;

New Delhi, Agency: When many senior advocates have political leanings and some of them represent political parties as members of Parliament, political viewpoints seamlessly sneak in as banter even during the proceedings before the Supreme Court.During the hearing on appeals filed by civil servants who were dismissed by Assam govt on discovery of a pervasive cash-for-job scam in Assam Public Service Commission, senior advocate Menaka Guruswamy, who is also TMC MP in Rajya Sabha, on Thursday told a bench of Justices Ahsanuddin Amanullah and R Mahadevan that the court had an unusually heavy cause list of 83 cases. When Justice Amanullah said the daily case list often exceeds 100, Guruswamy took the opportunity to take a political dig at the NDA govt and remarked that the cause list matches the rising petrol and diesel prices and the depreciation of value of rupee against dollar, both hovering around the figure of 100 at present and which is a go to issue for opposition to criticise the Centre.

'I, Vadasseri Damodara Menon Satheesan': Why Kerala Congress leaders are not happy with their own CM

New Delhi, Agency: In four days of securing Kerala chief minister post, Congress leader VD Satheesan has found himself at the centre of a political storm that is not over policy or governance, but over his name.Congress leaders have now criticised its own CM for the name he chose to publicly use while taking his constitutional oaths.

The row erupted after Satheesan used his full legal name, 'Vadasseri Damodara Menon Satheesan', while taking oath as chief minister on May 18 and again while taking oath as an MLA of the 16th Kerala legislative assembly on Thursday.

What's in the name?

The controversy stems largely from the contrast with Satheesan's earlier public political identity.When he took oath as an MLA in 2021, he had identified himself simply as 'VD Satheesan'. This time, however, he chose to use the expanded version of his name at two high-profile constitutional ceremonies. 'Menon' surname belongs to the upper caste Nair community in Kerala.

'Vande Mataram' from top of the world: BSF's first all-women team conquers Everest

New Delhi, Agency: An all-women Border Security Force (BSF) mountaineering team on Thursday created a record by scaling Mount Everest, marking the feat by singing "Vande Mataram" from the world's highest peak, a spokesperson of the border-guarding force said.

The team comprised constable Kouser Fatima from Ladakh, constable Munmun Ghosh from West Bengal, constable Rabeka Singh from Uttarakhand and constable Tsering Chorol from Kargil. They successfully summited the 8,848.86-metre peak at 8 am (IST) on Thursday.

The mountaineers also sang the national song from the summit, the BSF spokesperson said, adding that the expedition was a tribute to the 150th anniversary of "Vande Mataram" in 2026.

Anil Agarwal Advocates Bihar IPL Team to Boost Local Cricket Talent

DB Reporter

Patna : Anil Agarwal, Chairman of the Vedanta Group, has strongly advocated the creation of an Indian Premier League (IPL) franchise for Bihar, saying the state possesses exceptional cricketing talent and deserves a stronger presence on the national sporting stage.Speaking about Bihar's rich contribution to Indian cricket, Agarwal said that just as teams like Chennai Super Kings, Mumbai Indians and Kolkata Knight Riders have become symbols of regional pride, Bihar too should have a competitive and respected team representing the state in the IPL.He highlighted several cricketers from Bihar who

have made a mark at the national level. Among them is Ishan Kishan from Patna, who created history with one of the fastest double centuries in One Day International cricket. Agarwal also praised Vaibhav Suryavanshi of Samastipur, one of the youngest players to debut in the IPL, and Saqib Hussain from Gopalganj, whose bowling performances have drawn attention from cricket followers across the country.Despite producing talented players, Bihar has not yet received the recognition, infrastructure and opportunities commensurate with its cricketing potential, he said. Agarwal stressed the need for world-class training facilities, advanced coaching systems and a robust support network within the state to nurture emerging talent.Expressing confidence in Bihar's youth, he said that with the right guidance, resources and motivation, a Bihar-based team could become one of the most competitive and inspiring sides in Indian cricket. Reaffirming his commitment, Agarwal pledged unconditional support for initiatives aimed at developing cricket in the state.

No rationing of fuel, bulk consumers leading to long queues: Govt

NEW DELHI: Dismissing reports of any shortage, govt on Thursday asserted that there was no rationing of petrol and diesel anywhere in the country and attributed long queues at fuel pumps in some parts to bulk diesel consumers, such as industries, shifting to retail outlets due to a price gap of nearly Rs 42 a litre. Sujata Sharma, joint secretary in petroleum and natural gas ministry, said sales at retail pumps had risen with the onset of the kharif sowing season, while consumers buying from private outlets had shifted to PSU-owned pumps

because of price differences in auto fuel. She said a 20-30% increase in sales had been observed at retail pumps in certain parts of the country."The ministry has done an analysis...oil marketing companies are monitoring the situation. We have sufficient supplies of fuel, and all steps are being taken to maintain them," Sharma said, while urging the public to avoid panic buying.

Govt plans childhood cancer registry as India battles 75,000 new cases a year

New Delhi, Agency: The Ministry of Health and Family Welfare is working with the Indian Council of Medical Research (ICMR) on a nationwide system for early detection and reporting of childhood cancer, including a possible registry and making the disease notifiable, amid concern over delayed diagnosis and low survival rates among children in India."One of the key priorities in childhood cancer care is early detection. Setting up a registry for childhood cancer and declaring it a notifiable disease is an issue. We are still working with ICMR on this. The aim is not to miss any patient," said Leimapokpam Swasticharan, Deputy Director General, Directorate General of Health Services (DGHS), on Thursday.The move comes as India records an estimated 75,000 new childhood cancer cases annually, while survival rates remain below 60%, according to experts and studies cited at a national workshop organised by the Indian Childhood Cancer Initiative (ICCI).Calling childhood cancer a "low hanging fruit" in improving cancer survival outcomes, Dr Swasticharan said the government's existing non-communicable disease (NCD) programme already includes a cancer component, but the immediate focus is on identifying children early and ensuring treatment support reaches them in time.

"The priority is that a childhood cancer patient should be detected early and

get financial support and medical care," he said.He also suggested adopting successful district level models from Kerala and Tamil Nadu, including innovative financing mechanisms and community participation through self-help groups.Former NITI Aayog Member (Health) Dr V.K. Paul said India's biggest challenge is enabling families and frontline workers to recognise symptoms early enough for treatment to begin before the disease advances.